Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

डाक पंजीयन संख्याः-एल-2/9/रजि0/ए0डी0/119/15-17

संस्करण : लखनऊ
वर्ष : 11
अंक : 251
पृष्ठ : 6
मूल्य : 1.00
लखनऊ-गुरूवार ,08 जनवरी 2026

हिन्दी दैनिक

मंत्र भारत

लखनऊ, प्रयागराज ,ग्वालियर एवं मुम्बई से एक साथ प्रकाशित एवं गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ से प्रसारित

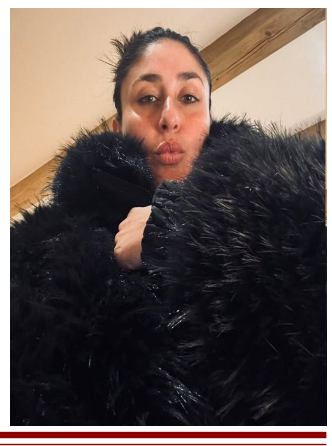

3 लखनऊ में पारंपरिक पसंदीदा व्यंजनों के साथ

4 सोमनाथ के शिखर पर फहराती ध्वजा गवाह है, आतंक

5 बर्फ से ढकी पहाड़ियां, सर्दियों का खूबसूरत नजारा..करीना कपूर ने शेयर

यूपी सरकार का बड़ा फैसला

असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को निरस्त करने का दिया आदेश

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में होने वाली समस्त भर्तियों/चयन प्रक्रियाओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण बनाए रखने के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता के अनुरूप नकल माफियाओं के विरुद्ध अभिसूचना संकलन करते हुए एसटीएफ उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या-51 के अंतर्गत सहायक आचार्य पद हेतु अप्रैल 2025 में आयोजित परीक्षा के संबंध में अनियमितताओं/धांधली एवं अवैध धन वसूली से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश द्वारा मामले की गोपनीय जांच के आदेश दिए गए। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 20-04-2025 को यूपी एसटीएफ को उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा दिनांक 16-04-2025 व 17-04-2025 को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का फर्जी प्रश्नपत्र बनाकर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले गैंग के तीन अभियुक्तों- महबूब अली, बैजनाथ पाल एवं विनय पाल-को परीक्षा में धांधली एवं अवैध धन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आयोग की अध्यक्ष से त्यागपत्र लिया जा चुका है इस संबंध में यूपी एसटीएफ द्वारा थाना विभूतिखंड, जनपद लखनऊ पर मु.अ.सं. 144/25, धारा 112, 308(5), 318(4) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), 2023, अभियोग पंजीकृत कराया गया। जांच की निष्पक्षता एवं गोपनीयता सुनिश्चित रखने के उद्देश्य से तत्कालीन आयोग की अध्यक्ष से त्यागपत्र लिया गया था चूंकि अभियुक्त महबूब अली निवर्तमान आयोग की अध्यक्ष का गोपनीय सहायक था। पूछताछ के दौरान अभियुक्त महबूब अली ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा मॉडरेशन प्रक्रिया के दौरान ही विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र निकाल लिए गए थे, जिन्हें उसने कई अभ्यर्थियों को विभिन्न माध्यमों से धन लेकर उपलब्ध कराया। अभियुक्त महबूब अली की स्वीकारोक्ति की एसटीएफ द्वारा गहन विवेचना एवं डेटा एनालिसिस से पुष्टि हुई है। जांच में परीक्षा की शुचिता भंग होने की पुष्टि हुई जांच के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्तों तथा उनसे संबंधित अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबरों का डाटा विश्लेषण एवं मुखबिर तंत्र से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम एवं मोबाइल नंबर प्रकाश में आए। इस संबंध में आयोग को पत्र लिखकर संदिग्ध अभ्यर्थियों का डाटा मांगा गया। प्राप्त डाटा के मिलान में यह तथ्य सामने आया कि उक्त परीक्षा की शुचिता भंग हुई है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री योगी द्वारा उक्त परीक्षा को निरस्त किए जाने के आदेश दिये गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देशित किया है कि उपरोक्त परीक्षा का आयोजन शीघ्रातिशीघ्र, पूर्णतः निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित किया जाए।

अंकिता भंडारी के माता-पिता से जल्द मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री धामी, जांच को लेकर करेंगे बात

देहरादून (एजेंसी)। सीएम पुष्कर सिंह धामी जल्द अंकिता के माता-पिता से मिलेंगे। सीएम उनसे बात कर जांच की दिशा किस तरह की रखी जाए और वह सरकार से क्या चाहते हैं, के बारे में उनके विचार जानेंगे। सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात दून में जल्द होगी। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय कर दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि इस संबंध में अंकिता के माता-पिता से मैं स्वयं बात करूंगा, वह न्याय के लिए जो चाहते हैं, सरकार उनकी भावनाओं के आधार पर आगामी निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि एक ऑडियो से प्रदेश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उससे सबसे ज्यादा अंकिता का परिवार प्रभावित हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की सत्यता जानने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। सबूत होने पर कोई भी दोषी कार्रवाई से बच नहीं पाएगा। पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता व पारदर्शिता के साथ कार्य किया: सीएम अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पहली बार मुख्यमंत्री धामी ने प्रेसवार्ता में सरकार की मंशा को स्पष्ट किया। कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इस दिशा में सरकार ने पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता व पारदर्शिता के साथ कार्य किया है। सरकार की सशक्त और प्रभावी पैरवी के कारण ही तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है मुख्यमंत्री ने कहा, इस जघन्य अपराध की निष्पक्ष व गहन जांच के लिए महिला आईपीएस अधिकारी रेणुका देवी की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था, जिसने मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की। एसआईटी की ओर से जांच के दौरान लोगों से साक्ष्य मांगे गए थे। इसके बाद सरकार ने न्यायालय में भी मामले की सशक्त व प्रभावी पैरवी की। एसआईटी की जांच पर निचली अदालत व उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने भी संतोष व्यक्त किया है, जो जांच की निष्पक्षता और मजबूती को दर्शाता है।

'सोमनाथ से सबसे अधिक नफरत पंडित नेहरू को थी':भाजपा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रुख की कड़ी आलोचना की है। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि महमूद गजनवी और अलाउद्दीन खिलजी जैसे ऐतिहासिक आक्रांताओं ने तो मंदिर को केवल भौतिक रूप से लूटा था, लेकिन नेहरू के मन में भगवान सोमनाथ के प्रति सबसे ज्यादा घृणा थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा करते हुए त्रिवेदी ने नेहरू द्वारा कथित तौर पर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को लिखे गए एक पत्र को साझा किया। त्रिवेदी ने दावा किया कि, इस पत्र में नेहरू ने खान को 'प्रिय नवाबजादा' कहकर संबोधित किया और सोमनाथ के दरवाजों की कथा को पूरी तरह झूठा बताया। हिंदू ऐतिहासिक प्रतीकों को कम आंकाः भाजपा भाजपा नेता का तर्क है कि यह पत्र एक प्रकार का आत्मसमर्पण था, जिससे यह संकेत मिलता है कि नेहरू ने भारत की सभ्यतागत विरासत की रक्षा करने के बजाय मंदिर के पुनर्निर्माण को कम महत्व देने की कोशिश की।

नंदीग्राम आंदोलन से बंगाल में उखड़ी थी तीन दशकों की वाम सत्ता

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए प्रदर्शनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 2007 में पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में हुई गोलीबारी की घटना में तीन भूमि अधिग्रहण विरोधी प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। भाजपा नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'शहीद तर्पण दिवस 7 जनवरी, 2007 के अवसर पर मैं नंदीग्राम भूमि रक्षा आंदोलन के तीन अमर शहीदों को अपनी श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।' नंदीग्राम में खेजुरी और सोनाचुरा के बीच भांगा बेरा ब्रिज क्षेत्र के पास स्मारक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस घटना ने राज्य में व्यापक अशांति को जन्म दिया और अंततः पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जिसने वाम मोर्चा सरकार के पतन में योगदान दिया। नंदीग्राम में बुधवार को भाजपा और स्थानीय टीएमसी नेताओं ने भी इस घटना में मारे गए लोगों को याद करने के लिए शहीद दिवस मनाया।

बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले की मुखबिर ने एनसीपी में शामिल हुई

महाराष्ट्र (एजेंसी)। महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले का खुलासा करने वाली एक महिला मुखबिर अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में शामिल हो गई है। संगीता चंदवंकर, जिन्होंने पहले बदलापुर में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) की महिला शाखा का नेतृत्व किया था। उन्होंने मंगलवार को शहर में एक समारोह में एनसीपी में शामिल किया गया। राज्य में विभिन्न नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं। बदलापुर स्कूल मामले में मुख्य मुखबिर के रूप में प्रसिद्धि मिली अगस्त 2024 में चेंदवंकर को बदलापुर स्कूल मामले में मुख्य मुखबिर के रूप में प्रसिद्धि मिली। बदलापुर में कथित तौर पर दो 4 वर्षीय बच्चियों के साथ एक संविदा सफाईकर्मी द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था। उन्होंने अभिभावकों को एकजुट करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि मामला पुलिस और जनता तक पहुंचे।

ट्रंप के टैरिफ को लेकर राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना

इंदिरा गांधी का जिक्र कियाःराहुल

नई दिल्ली (एजेंसी)। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। राहुल गांधी ने उन पर दबाव के आगे झुकने का आरोप लगाया और उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व से की। राहुल गांधी की यह टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के एक दिन बाद आई। रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों की बैठक में ट्रंप ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा- सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? जी हां। ट्रंप ने भारत पल लगाए गए भारी टैरिफ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत अभी 'बहुत ज्यादा टैरिफ' चुका रहा है और उसने रूसी तेल की खरीद 'काफी हद तक कम' कर दी है। राहुल गांधी ने इस बयान से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया, जिसका कैप्शन 'फर्क समझो सरजी' था। 'ट्रंप ने इशारा किया, आत्मसमर्पण

कर दिया..' राहुल गांधी ने कहा, मैं अब इन भाजपा-आरएसएस के लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का दो और ये डर के मारे भाग जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, जैसे ही ट्रंप ने वहां से इशारा किया, इन्होंने फोन उठा लिया। उन्होंने कहा, 'मोदी जी आप क्या कर रहे हैं?' नरेंद्र ने सरेंडर (आत्मसमर्पण) कर दिया और 'जी हुजूर' कहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया।' 1971 के युद्ध का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एक समय भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद मजबूती से अपना रुख बनाए रखा था। उन्होंने कहा, आपको वह समय याद होगा जब केवल फोन कॉल नहीं आया था- सातवां बेड़ा आ गया था। 1971 के युद्ध में सातवां बेड़ा आया, हथियार आए, एक विमानवाहक पोत आया। तब इंदिरा गांधी जी ने कहा था, 'मुझे जो करना है, मैं करूंगी।' यही फर्क है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा था? डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कुल 50 फीसदी तक के टैरिफ लगाए हैं। इसमें 25 फीसदी रूस से तेल की खरीद को लेकर लगाया गया है। ट्रंप ने कहा, मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। वो मुझसे बहुत खुश नहीं हैं क्योंकि वे अभी बहुत ज्यादा टैरिफ चुका रहे हैं।

मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने पर असंतोष

गृह मंत्री ने पुलिस पर पत्थरबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद तुर्कमान गेट के पास सैयद फैज इलाही मस्जिद के आसपास तोड़फोड़ करने से स्थिति बिगड़ गई है। एमसीडी के द्वारा देर रात अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने पुलिस पर पत्थरबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि अतिक्रमण हटाने की पूरी प्रक्रिया अदालत के आदेशों के बाद की गई है, इसका विरोध करना अनुचित है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। गृह मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में किसी वैध इमारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन मस्जिद के आसपास लोगों ने अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर दिया था। इससे लोगों का आवागमन बाधित हो रहा था। उन्होंने कहा कि इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के आदेशों के अनुसार की जा रही है। कानून के दायरे में हो रहे कार्य को रोकना या उसमें बाधा डालना पूरी तरह गलत है। सूद ने कहा कि इस घटना के बाद कुछ शरारती तत्वों ने एमसीडी के काम में बाधा डालने की कोशिश की। पुलिस बल पर हिंसा की गई और कार्रवाई को रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि इस आपत्तिजनक हरकत में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अन्य शरारती तत्वों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। मस्जिद सुरक्षित तो विरोध क्यों गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि फैज ए इलाही मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कार्रवाई केवल अवैध अतिक्रमण पर की जा रही है।

कांग्रेस-ओवैसी से भाजपा के गठबंधन पर भड़के फडणवीस

किसी भी कीमत पर स्वीकार नहींःफडणवीस

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अंबरनाथ और अकोला में कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएम आईएम) के साथ गठबंधन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए इस गठबंधन को खारिज किया है। अंबरनाथ में भाजपा ने कांग्रेस और अजित पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन कर नगर परिषद का अध्यक्षता बनाया है। वहीं अकोट नगर परिषद में भाजपा ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया है। सीएम फडणवीस ने स्थानीय भाजपा इकाई के इस कार्य को संगठन विरोधी बताया है। साथ ही कड़ी नाराजगी जताते हुए ऐसे गठबंधन को तुरंत खत्म करने के बाद पार्टी के निदेर्शों का उल्लंघन करने वाले नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघनः फडणवीस गठबंधन को खारिज करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस तरह के किसी भी तरह के गठबंधनों को पार्टी

के वरिष्ठ नेतृत्व की मंजूरी नहीं है। यह संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन है। अपने बयान में सीएम ने कहा कि भाजपा कभी भी कांग्रेस या एआईएमआईएम के साथ गठबंधन नहीं कर सकती। ऐसे गठबंधन अस्वीकार्य हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश मुख्यमत्री फडणवीस ने अपने बयान में कहा कि ऐसे गठबंधन को को रद्द करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं और यह भी कहा कि इसमें शामिल नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

'तमिलनाडु में हिंदुओं के अधिकार छीने जाने का आरोप झूठ', सीएम स्टालिन का अमित शाह पर पलटवार

दिंडीगुल (तमिलनाडु) (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अमित शाह के हिंदुओं के अधिकार छीने जाने के आरोप को खारिज किया। स्टालिन ने कहा राज्य में सभी धर्मों के अधिकार सुरक्षित हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का राज्य में हिंदुओं के अधिकार छीने जाने का आरोप पूरी तरह झूठा और उनकी पदवी के अनुकूल नहीं है। एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा हमारे राज्य में सभी धर्मों के लोगों के विश्वास और धार्मिक

अधिकारों का पूरा सम्मान किया जाता है। ऐसे में गृहमंत्री का यह आरोप कि हिंदुओं के अधिकार छीने जा रहे हैं, पूरी तरह गलत और अनुचित है। यह वही मानसिकता है जो दंगे और विघटन चाहती है, लेकिन तमिलनाडु में उसे कोई सफलता नहीं मिली। स्टालिन ने आगे कहा ऐसा भविष्य में कभी नहीं होने दिया जाएगा। जब तक मैं स्टालिन हूं, यह बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। 'हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार' इससे पहले रविवार को पुदुकोट्टई में एक सार्वजनिक सभा में अमित शाह ने डीएमके सरकार पर हिंदू धर्म और भावनाओं का लगातार अपमान करने का आरोप लगाया था।

शशि थरूर ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ साझा की तस्वीर, लक्ष्य समिट के दौरान हुई चर्चा

वायनाड (केरल) (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि उन्हें केरल के वायनाड में आयोजित दो दिवसीय लक्ष्य लीडरशिप समिट में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत का अनुभव बहुत अच्छा लगा। थरूर ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर साझा किया कि इस समिट में उन्होंने कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, केरल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन और अन्य वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। उन्होंने कहा समिट में औपचारिक बैठकों के बाहर अनौपचारिक बातचीत करना बहुत अच्छा अनुभव रहा। पूरे राज्य के सहकर्मियों से मिलने का अवसर भी मिला। समिति में

एकजुटता और चुनाव तैयारी थरूर ने बताया कि समिट केरल विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की ताकत और एकजुटता दिखाने के लिए आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनावों के परिणामों से नया उत्साह और आत्म विश्वास महसूस कर रही है, लेकिन संतोष का समय नहीं है, और अब कड़ी मेहनत की जरूरत है। थरूर ने आगामी 100 दिनों को निर्णायक बताया और कहा कि कांग्रेस और यूडीएफ को न केवल सरकार पर सवाल उठाने बल्कि सकारात्मक एजेंडा और संदेश बनाने पर भी ध्यान देना होगा।

आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोट

पुणे (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में दो आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर जवाब मांगा, जिसमें मई 2024 में दो लोगों की जान चली गई थी। आदित्य अविनाश सूद (52) और आशीष सतीश मित्तल (37) को पिछले साल 19 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि दुर्घटना में शामिल दो नाबालिगों की जगह उनके खून के सैंपल जांच के लिए इस्तेमाल किए गए थे। बता दें कि 19 मई, 2024 को पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक पोर्श कार ने दो लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे के वक्त

कार कथित तौर पर शराब के नशे में एक 17 साल का लड़का चला रहा था। जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयॉन की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। पिछले साल 16 दिसंबर को हाईकोर्ट ने इस मामले में सूद और मित्तल सहित आठ आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। कोर्ट ने कर दिया था रिहा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को आसान शर्तों पर जमानत दे दी थी, जिससे पूरे देश में अक्रोश देखने को मिला था। जमानत की शर्तों में रोड सेफ्टी पर 300 शब्दों का निबंध लिखना शामिल था। फैसले की आलोचना होने के बाद पुणे पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए संपर्क किया। इसके बाद बोर्ड ने आदेश में बदलाव किया और नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया। जून में हाईकोर्ट ने नाबालिग को रिहा करने का आदेश दिया था। आदित्य सूद ने अल्कोहल परिक्षण में धोखा देने की कोशिश की आदित्य सूद उन 10 लोगों में शामिल थे, जिन्हें किशोर चालक के अल्कोहल परीक्षण को रद्द करने के लिए रक्त के नमूनों की अदला-बदली के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

मंत्र भारत

पूर्वांचल

लखनऊ-गुरूवार ,08 जनवरी 2026

महाप्रबन्धक सभाकक्ष, गोरखपुर में कार्य समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे उदय बोरवणकर

गोरखपुर,: महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे श्री उदय बोरवणकर की अध्यक्षता में महाप्रबन्धक सभाकक्ष, गोरखपुर में 07 जनवरी, 2026 को आयोजित कार्य समीक्षा बैठक में महाप्रबन्धक श्री उदय बोरवणकर ने पूर्वोत्तर रेलवे पर संरक्षा, सुरक्षा, यात्री सुविधा, यातायात सुविधा एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धित कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्लान हेड 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 42, 51, 53, 64 एवं 65 के अन्तर्गत यात्री सुविधा के विकास एवं विस्तार हेतु समपारों पर संरक्षा के सुदृढ़ीकरण, कर्मचारियों हेतु नये रेल आवासों, शेडों के विकास, वंदे भारत एक्सप्रेस के रेक के अनुरक्षण, पार्सल एवं गुड्स शेड के कार्य, दिव्यांगजन हेतु सुविधाओं, फुट ओवर ब्रिज (एफ.ओ.बी.) पर रैम्प, प्लेटफॉर्मों का उच्चीकरण एवं विस्तार, संरक्षा एवं सुरक्षा के कार्य, कैटल रन ओवर (सी.आर.ओ.) से बचाव, बैरकों का निर्माण, क्षमता विस्तार के कार्य, स्टेशनों पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था के लिये हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था आदि विभिन्न विषयों पर विस्तारित चर्चा हुई।

इस अवसर पर अपर महाप्रबन्धक श्री विनोद कुमार शुक्ल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण श्री अभय कुमार गुप्ता, प्रमुख मुख्य इंजीनियर श्री नीलमणि, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबन्धक श्री राजेश कुमार, प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक श्री प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिरीक्षक-सह-प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेलवे सुरक्षा बल श्री सत्य प्रकाश, प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री नरेश कुमार, प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर श्री एम.एल. मकवाना, प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर श्री संजय सिंघल, प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक श्री ए.ए. खान, मुख्य इंजीनियर/निर्माण/आर.एस.पी. श्री राजीव कुमार, मुख्य इंजीनियर/पी एंड डी श्री आशीष श्रीवास्तव, मुख्य कार्मिक अधिकारी/आई.आर. श्री मनोज कुमार पांडेय, मंडल रेल प्रबन्धक/लखनऊ श्री गौरव अग्रवाल, मंडल रेल प्रबन्धक/वाराणसी श्री आशीष जैन, मंडल रेल प्रबन्धक/इज्जतनगर सुश्री वीणा सिन्हा एवं वरिष्ठ रेल अधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुये महाप्रबन्धक श्री उदय बोरवणकर ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे पर चल रही निर्माण परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करें तथा लम्बित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यों में तेजी लाकर पूरा किया जाये। उन्होंने कहा कि रेलवे के सभी पोर्टल की नियमित आधार पर मॉनिटरिंग की जानी चाहिये, जिससे रेलवे की कार्यप्रणाली सुचारू रूप से कार्यरत रहे। श्री बोरवणकर ने कहा कि कार्यों को पूर्ण करने हेतु उचित योजना बनाया जाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर सही तरीके से योजना बना ली तो समझो कि आधा काम पूरा हो गया है। महाप्रबन्धक ने कहा कि सभी परियोजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे पर चल रही अन्य निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रमुख मुख्य इंजीनियर श्री नीलमणि ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्लान हेड के अनुसार परियोजनाओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

प्रायोगिक आधार पर 02 मिनट का ठहराव निम्नवत प्रदान किया जायेगा

गोरखपुर,: रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु 14627/14628 सहरसा-छेहरटा-सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस का लक्सर स्टेशन पर प्रायोगिक आधार पर 02 मिनट का ठहराव निम्नवत प्रदान किया जायेगा।

प्रायोगिक ठहराव-

-सहरसा से 12 जनवरी, 2026 से चलने वाली 14627 सहरसा-छेहरटा अमृत भारत एक्सप्रेस लक्सर स्टेशन पर 18.32 बजे पहुँचकर 18.34 बजे प्रस्थान करेगी।

-छेहरटा से 17 जनवरी, 2026 से चलने वाली 14628 छेहरटा-सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस लक्सर स्टेशन पर 06.21 बजे पहुँचकर 06.23 बजे प्रस्थान करेगी।

अजमेर से 12 जनवरी, 2026 से चलने वाली 15716 अजमेर-किशनगंज एक्सप्रेस किशनगढ़ स्टेशन पर 12.27 बजे पहुँचकर 12.29 बजे प्रस्थान करेगी

गोरखपुर,: रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर एवं जयपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर निम्नलिखित गाड़ियों का प्रायोगिक आधार पर 02 मिनट का ठहराव निम्नवत प्रदान किया जायेगा।

प्रायोगिक ठहराव-

-साबरमती से 10 जनवरी, 2026 से चलने वाली 19409 साबरमती-थावे एक्सप्रेस पिण्डवाड़ा स्टेशन पर 14.13 बजे पहुँचकर 14.15 बजे प्रस्थान करेगी।

-थावे से 10 जनवरी, 2026 से चलने वाली 19410 थावे-साबरमती एक्सप्रेस पिण्डवाड़ा स्टेशन पर 05.54 बजे पहुँचकर 05.56 बजे प्रस्थान करेगी।

-पोरबंदर से 09 जनवरी, 2026 से चलने वाली 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस किशनगढ़ स्टेशन पर 12.22 बजे पहुँचकर 12.24 बजे प्रस्थान करेगी।

-मुजफ्फरपुर से 11 जनवरी, 2026 से चलने वाली 19270 मुजफ्फरपुर-पोरबंदर एक्सप्रेस किशनगढ़ स्टेशन पर 20.11 बजे पहुँचकर 20.13 बजे प्रस्थान करेगी।

-किशनगंज से 11 जनवरी, 2026 से चलने वाली 15715 किशनगंज-अजमेर एक्सप्रेस किशनगढ़ स्टेशन पर 20.17 बजे पहुँचकर 20.19 बजे प्रस्थान करेगी।

-अजमेर से 12 जनवरी, 2026 से चलने वाली 15716 अजमेर-किशनगंज एक्सप्रेस किशनगढ़ स्टेशन पर 12.27 बजे पहुँचकर 12.29 बजे प्रस्थान करेगी।

सब-वे निर्माण हेतु गर्डर लांचिंग के परिप्रेक्ष्य में ब्लॉक लिये जाने के कारण गाड़ियों का नियंत्रण निम्नवत रहेगा

गोरखपुर, : रेलवे प्रशासन द्वारा परिचालनिक सुगमता हेतु वाराणसी मंडल के रजवारी-कादीपुर स्टेशनों के मध्य समपार संख्या-09 पर सीमित ऊँचाई के सब-वे निर्माण हेतु गर्डर लांचिंग के परिप्रेक्ष्य में ब्लॉक लिये जाने के कारण गाड़ियों का नियंत्रण निम्नवत रहेगा।

नियंत्रण-

-55131 बलिया-प्रयागराज रामबाग सवारी गाड़ी 10 एवं 16 जनवरी, 2026 को मार्ग में 60 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी।

-65109 आजमगढ़-वाराणसी सिटी मेमू गाड़ी 10 एवं 16 जनवरी, 2026 को मार्ग में 30 मिनट नियंत्रित कर चलाई जायेगी।

यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही बचपन बचाओ अभियान के तहत मानव तस्करी की रोकथाम का निरंतर प्रयास किया जाता है

गोरखपुर,: रेलवे सुरक्षा बल, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा, रेल सम्पत्ति की सुरक्षा, अवैध सामानों की धर-पकड़, यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही बचपन बचाओ अभियान के तहत मानव तस्करी की रोकथाम का निरंतर प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में, राजकीय रेलवे पुलिस एवं अपराध आसूचना शाखा, कासगंज द्वारा संयुक्त निगरानी के दौरान 05 जनवरी, 2026 को गाड़ी सं0 19410 के रेलवे स्टेशन कासगंज यार्ड में प्रवेश करते समय गाड़ी पर पत्थर मारने वाले 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 05 जनवरी, 2026 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट वाराणसी सिटी द्वारा निगरानी के दौरान रेलवे स्टेशन सारनाथ उत्तरी साइड पुराने केबिन के पास से चोरी कर पूर्व में ही छुपाये हुए रेल सम्पत्ति (41 मीटर कॉपर वायर) को ले जाते समय एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। 04 जनवरी, 2026 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट सीतापुर को निगरानी के दौरान गाड़ी सं0 15531 में 16 वर्ष का एक नाबालिग लड़का लावारिस हालत में मिला, जिसे उतारकर सीतापुर पोस्ट पर लाया गया। पूछताछ के उपरान्त उक्त लड़के को चाइल्ड लाइन, सीतापुर को सुपुर्द किया गया। 05 जनवरी, 2026 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गाजीपुर सिटी को निगरानी के दौरान गाड़ी सं0 19051 में 17 वर्ष का एक लड़का लावारिस हालत में मिला, जिसे उतारकर गाजीपुर सिटी पोस्ट पर लाया गया। पूछताछ के उपरान्त उक्त लड़के को चाइल्ड लाइन, गाजीपुर सिटी को सुपुर्द किया गया। 29 नवम्बर, 2025 को गाड़ी सं0 14005 के रेलवे सुरक्षा बल स्कोर्ट द्वारा निगरानी के दौरान यात्री का छूटा मोबाइल एवं चार्जर मिला, जिसे रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट बनारस पर जमा किया गया। 06 जनवरी, 2026 को यात्री के पोस्ट पर उपस्थित होने पर उचित पहचान व सत्यापन के उपरान्त मोबाइल एवं चार्जर सुपुर्द किया गया। 12 दिसम्बर, 2025 को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गोमतीनगर को निगरानी के दौरान गाड़ी सं0 13435 में महिला यात्री का छूटा ट्राली बैग मिला, जिसे गोमतीनगर पोस्ट पर जमा कराया गया। 05 जनवरी, 2026 को महिला यात्री के परिचित के पोस्ट पर उपस्थित होने पर उचित पहचान व सत्यापन के उपरान्त ट्राली बैग सुपुर्द किया गया।

दो साल बीते झकरकटी बस अड्डा नहीं हो सका शिफ्ट

कानपुर। 143 करोड़ की झकरकटी बस अड्डा योजना एलिवेटेड रोड के रैंप और जमीन शिफ्टिंग के विवाद में अटक गई है। ठेकेदार कंपनी और परिवहन विभाग के बीच समन्वय की कमी से साल 2026 में भी काम शुरू होना चुनौतीपूर्ण लग रहा है। कानपुर में झकरकटी बस अड्डा निर्माण का कार्य साल 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। योजना को बने दो साल से ज्यादा समय हो गया लेकिन इसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका है। मामला अभी भी ठेकेदार कंपनी और परिवहन निगम के बीच इसकी शिफ्टिंग पर अटका है। अगर यह कार्य शुरू भी हुआ तो इसके आधुनिक रूप लेने में दो साल और लगेंगे। पीपीपी मॉडल के तहत झकरकटी बस अड्डा का पुनर्विकास कार्य 143 करोड़ से होना है। करीब दो साल पहले योजना बनी और इसका ठेका पंजाब की सीगल कंपनी को दिया गया। इसके लिए झकरकटी बस अड्डा दो साल के लिए दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। सीओडी पुल के पास रक्षा विभाग की जमीन देखी गई लेकिन रक्षा संपदा विभाग ने अधिक पेड़ होने का हवाला देकर इन्कार कर दिया। इसके बाद रेल बाजार थाने के सामने, पराग दूध डेयरी के पास रेलवे ग्राउंड और केडीए से जमीन देने के लिए कहा गया। अब मामला फिर अटक गया है इस दौरान ठेकेदार कंपनी भी हीलाहवाली करती रही और परिवहन विभाग के साथ बैठक करने नहीं आई। मुख्यालय से सख्ती हुई तो आनन-फानन में परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बस अड्डा सिग्नेचर सिटी ले जाने की हामी भर दी। सब कुछ तय हो गया तो कंपनी ने नया अड़ंगा लगा दिया कि रामादेवी से गोल चौराहा तक एलिवेटेड रोड बनना है। इसका रैंप झकरकटी के पास उतरेगा। इस वजह से बस अड्डा के प्रवेश द्वार पर रैंप आ जाएगा। चार फीट की जगह की वजह से अब शिफ्टिंग नहीं हो रही है। अब मामला फिर अटक गया है। ये होंगी सुविधाएं यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, फूड जोन, मल्टीप्लेक्स, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट। 16 प्लेटफॉर्म होंगे जिनमें एसी और नॉन-एसी दोनों प्रकार की बसें चलेंगी। बड़ी स्क्रीन पर बसों के आने-जाने का समय और प्लेटफॉर्म नंबर प्रदर्शित होगा। 55183 वर्ग मीटर क्षेत्र में से 45 प्रतिशत हिस्सा व्यावसायिक उपयोग के लिए होगा। परिवहन निगम ने सिग्नेचर सिटी में बस अड्डे की शिफ्टिंग के लिए हामी भरी है। मुख्यालय भी ठेकेदार कंपनी से वार्ता कर काम शुरू करने को कह रहा है। जिला प्रशासन भी बस अड्डा शिफ्टिंग के लिए दूसरी जगह तलाश रहा है। भरोसा इसलिए नहीं ठेकेदार कंपनी अब बस अड्डा के मुख्य गेट पर चार फीट की जगह का अड़ंगा लगा रही है। परिवहन निगम माघ मेला तक बसों का संचालन झकरकटी से ही करने की घोषणा कर चुका है। जब तक बस अड्डा शिफ्ट नहीं होगा, निर्माण कार्य गति नहीं पकड़ सकेगा।

हैलट में दलालों का खेल हेपेटाइटिस पॉजिटिव को दी फर्जी निगेटिव रिपोर्ट

कानपुर। हैलट अस्पताल में दलालों ने हेपेटाइटिस-सी पॉजिटिव मरीज की फर्जी निगेटिव रिपोर्ट तैयार कर दी। आधे घंटे में रिपोर्ट मिलने पर शक हुआ और जांच में दलालों के गिरोह का पदार्फाश हो गया। हैलट में एक बार फिर दलालों के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। अस्पताल में भर्ती हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव रोगी को पैथोलॉजियों के दलाल ने फर्जी हेपेटाइटिस सी निगेटिव रिपोर्ट दे दी। ब्लड सैंपल लेने के आधे घंटे में दलाल ने फर्जी हेपेटाइटिस सी निगेटिव रिपोर्ट लाकर दे दी। एलाइजा जांच में तीन घंटे लगते हैं। मामले का खुलासा सर्जरी विभाग के एक प्रकरण की जांच में हुआ है। परिजनों ने इस संबंध में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की जांच टीम को लिखित बयान भी दिए हैं। सर्जरी विभाग में एक रोगी की सर्जरी होनी थी। एक सप्ताह पहले रात को ऑपरेशन के पहले रैपिड कार्ड से जांच की गई तो रिपोर्ट हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव मिला। इस पर वायरल लोड आदि की जांच के लिए जूनियर डॉक्टर ने एलाइजा जांच के लिए कहा। इस पर जूनियर डॉक्टर पर आरोप लगा कि उसने बाहर से जांच कराने के लिए कहा। इस पर प्राचार्य ने जांच कमेटी गठित कर दी। मंगलवार को जांच रिपोर्ट मिलने पर खुलासा हुआ कि जूनियर डॉक्टर ने कॉलेज से जांच के लिए कहा था। एलाइजा जांच में समय लगता है जूनियर डॉक्टर के पर्ची देते वक्त पैथोलॉजी के दलाल ने पता कर लिया। बाद में आकर रोगी का सैंपल और पैसा ले लिया। इसके आधे घंटे बाद फर्जी हेपेटाइटिस निगेटिव रिपोर्ट लाकर दे दी। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि सर्जरी के पहले हर रोगी की हेपेटाइटिस बी, सी और एचआईवी की रैपिड कार्ड से जांच कराई जाती है। पॉजिटिव आने पर दो-तीन बार जांच करके पुष्टि कर ली जाती है। इसे सत्यापित करने के लिए एलाइजा कराई जाती है। इस जांच में समय लगता है। सख्ती के अधिकारियों को निर्देश दिए सूत्रों का कहना है कि दलाल सैंपल लेकर जाते हैं और अपने मन से कंप्यूटर से रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं। रोगियों और उनके परिजनों को तो पता नहीं होता। जल्दी रिपोर्ट मिलने के भ्रम में रहते हैं। प्राचार्य डॉ. काला का कहना है कि इससे रोगी और डॉक्टर दोनों को नुकसान होता है। परिजन अस्पताल में जांचों की भरपूर सुविधा है। तीमारदार किसी के झांसे में न आएं। बाहरी लोगों के आने पर सख्ती के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं

प्रशासन ने रोपवे के वायरल ट्रॉली के वीडियो को बताया फर्जी

वाराणसी। वाराणसी में रोपवे की टेस्टिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर लोग सोशल मीडिया पर तरह- तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने इस वीडियो का सच बताया है। रोपवे की ट्रॉली की टेस्टिंग का वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर साझा किया गया। इसके जरिये सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सक्रियता दिखाई और वायरल वीडियो को फर्जी करार दिया। प्रशासन ने कहा कि यह परीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है। सोशल मीडिया में रोपवे के प्रसारित वीडियो में जो आप देख रहे हैं, यह पूरी तरह झूठ है। वाराणसी की रोपवे प्रणाली अंतरराष्ट्रीय मानकों, विशेष रूप से यूरोपीय सुरक्षा कोड के अनुसार डिजाइन की गई है। संचालन से पहले कठोर और विस्तृत सुरक्षा परीक्षण किए जाते हैं। एनएचएलएमएल की ओर से किया जा रहा यह ट्रायल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत और योजनाबद्ध परीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें आपातकालीन ब्रेकिंग, तेज हवा के दबाव की स्थिति, सेंसर की सक्रियता और अन्य परिस्थितियों में प्रणाली के सुरक्षित संचालन की जांच की जाती है। रोपवे हर स्थिति में सुरक्षित है। सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कमिश्नर बोले- लोड टेस्टिंग का हिस्सा मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने रोपवे के कैंट, विद्यापीठ और रथयात्रा स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद कहा कि रोपवे से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है।

मैदागिन-गोदौलिया मार्ग पर नहीं आएंगी वीआईपी गाड़ियां

वाराणसी। माघ मेला और पलट प्रवाह को लेकर वाराणसी में होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस व प्रशासन की टीमें सतर्क हैं। इसी क्रम में मैदागिन-गोदौलिया मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। माघ मेले को देख पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने मैदागिन-गोदौलिया मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित करने के साथ ही वीआईपी प्रोटोकॉल की एंट्री भी प्रतिबंधित कर दी है। वीआईपी गाड़ियां भी श्रीकाशी विश्वनाथ धाम की ओर से नहीं जा पाएंगी। मंगलवार को दोनों छोर पर बैरियर लगाए गए। प्रतिबंध में वीवीआईपी, वीआईपी, सेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस और प्रशासनिक वाहनों को भी शामिल किया गया है। व्यापारियों के दो पहिया को छूट मिलेगी। दिव्यांगों, गर्भवती और वरिष्ठ नागरिकों के लिए गोल्फ कार्ट की सुविधा रहेगी। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि माघ मेले के दौरान संभावित पलट-प्रवाह को देख श्रद्धालुओं व दर्शनार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व सुगम आवागमन के लिए मैदागिन से गोदौलिया चौराहे तक नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नो-व्हीकल जोन में केवल पैदल आवागमन की अनुमति होगी, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से दर्शन कर सकें। क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग और निरंतर निगरानी के निर्देश दिए गए।

संक्षिप्त खबरें

आरोग्य मेले की शिकायतों की जांच के निर्देश

बस्ती। स्वास्थ्य सेवाओं में और बेहतरी लाने, सरकारी योजनाओं को आम जन तक पंहुचाने के साथ ही नेशनल स्वास्थ्य कार्यक्रमों की बिंदुवार मंगलवार को सीडीओ सार्थक अग्रवाल ने समीक्षा की। सीडीओ की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में संस्थागत प्रसव कम होने पर उन्होंने चिंता जताई और प्रसव बढ़ाने के निर्देश दिए। सीडीओ ने कहा कि जिन अस्पतालों का एनक्यूएएस का मूल्यांकन बाकी है उन्हें तैयार कराएं। इसके अलावा रविवार को आयोजित होने वाले जन आरोग्य मेले में मिल रही शिकायतों को लेकर अधिकारियों को जांच करने के लिए कहा। नवजात शिशुओं के लिए एनबीएसयू व एसएनसीयू की उपयोगिता के लिए इनबार्न और आउटबार्न यूनिट में शिशुओं को भर्ती करने में कोई लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।

जिला स्तरीय चयन-ट्रायल में शामिल हुए कुश्ती खिलाड़ी

बस्ती। बलिया में 16 से 18 जनवरी तक आयोजित हो रही प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता के लिए बस्ती की खिलाड़ियों का चयन-ट्रायल मंगलवार से शुरू हुआ। पहले दिन जिला स्तरीय चयन-ट्रायल में 20 खिलाड़ी प्रतिभाग किए। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि टीम खिलाड़ियों का चयन-ट्रायल जिले स्तर पर हुआ। मंडल स्तर पर सात जनवरी को शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में सुबह 11 बजे से चयन-ट्रायल होगा, जिसके बाद सफल खिलाड़ी टीम में शामिल किए जाएंगे।

आंगनबाड़ी केंद्र पर लगी एलईडी स्क्रीन

नगर बाजार। विकास खंड बस्ती सदर की ग्राम पंचायत मरहा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 योजना के तहत लाइट एमिटिंग डायोड स्क्रीन लगाया गया है। इस आधुनिक सुविधा से गांव के नन्हे बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जाएगा। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अखिल कुमार यादव ने बताया कि एलईडी स्क्रीन के माध्यम से बच्चों को रोचक, ज्ञानवर्धक एवं विकासात्मक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इससे सीखने की प्रक्रिया सरल, प्रभावी और आनंददायक बनेगी। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर शीघ्र ही वाटर कूलर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 योजना केंद्र एवं राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के तहत डिजिटल टूल्स का उपयोग, बेहतर निगरानी व्यवस्था, पोषण सहायता व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री के माध्यम से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा को सुदृढ़ किया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग

दुबौलिया। थाना क्षेत्र के राम जानकी मार्ग स्थित ललहवा के पास मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखे अधिकतर सामान जल गए। हादसे की जानकारी सुबह करीब 9 बजे बगल के दुकानदार ने दुकान मालिक को दी। इसके बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही दुकान संचालक मोहन पाण्डेय भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि, तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग लगने के कारणों का अब तक स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका।

सड़क हादसे में मौत के मामले में एफआईआर

बस्ती। शहर के मालवीय रोड पर सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में पुलिस ने मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुरानी बस्ती के पचपेड़िया निवासी विमला ने तहरीर देकर बताया है कि 28 दिसंबर 2025 की सुबह करीब आठ बजे उनके पति शत्रुघ्नन घर से निकले थे। जैसे ही वह कोतवाली के मालवीय रोड पर ब्राह्मण महासभा के करीब पहुंचे थे, तभी एक वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक उन्हें टक्कर मार दी। उन्हें गंभीर चोट आई और अस्पताल ले जाया गया। यहां देर रात करीब 11:30 बजे उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने वाहन चालक पर प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

लापता युवक की साइकिल तटबंध पर मिली

दुबौलिया। कस्बा निवासी राजू गुप्ता (27) शुक्रवार की सुबह करीब सात बजे घर से साइकिल से निकला था। काफी खोजबीन के बाद उसका पता नहीं चला। परिजनों ने चार जनवरी को उसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई थी। मंगलवार को युवक की साइकिल कटरिया-चांदपुर तटबंध के सरयू नदी के पास संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ी मिली। मौके पर लापता युवक के भाई राजेश कुमार ने पहुंचकर साइकिल की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने युवक की तलाश नदी में शुरू करा दी है।

मतदाता सूची के प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी, 16.02 लाख प्रपत्र डिजिटलाइज

बस्ती। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बस्ती में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन की प्रक्रिया मंगलवार को पूरी कर ली गई। प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जिले में 19,00,430 मतदाताओं के गणना प्रपत्र वितरित किए गए। इनमें से अब तक 16,02,143 मतदाताओं के प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन पूरा कर लिया गया है। डिजिटलाइज्ड किए गए मतदाताओं में 6,73,060 मतदाता (35.42 प्रतिशत) सेल्फ कैटेगरी में शामिल हैं। जबकि 8,17,411 मतदाता (43.01 प्रतिशत) प्रोजेनी कैटेगरी में दर्ज किए गए हैं। 14,90,471 मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग कर ली गई है। इससे मतदाता सूची की प्रामाणिकता को मजबूती मिली है। पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान 1,13,363 मतदाता ऐसे पाए गए, जिनका मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सका। प्रशासन के अनुसार, इन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी कर निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया छह जनवरी से 27 फरवरी तक चलेगी।

ओवर हाईट गन्ना लदे तीन वाहनों पर नौ हजार जुमार्ना

बनकटी। लालगंज पुलिस ने मंगलवार की देर शाम को बनकटी चौराहे के पास ओवरलोड व ओवर हाईट गन्ना लदे तीन वाहनों से तीन-तीन हजार रुपये का जुमार्ना लगाया। जानकारी के अनुसार, लालगंज थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने पुलिसकर्मियों के साथ बनकटी चौराहे पर ओवरलोड व ओवर हाईट गन्ना लदे दो ट्रालों से छह हजार व एक ट्रॉली पर तीन हजार रुपये का जुमार्ना लगाते हुए चालान कर दिया।

एसडीओ पर धमकाने के आरोप में प्राथमिकी

कप्तानगंज। कप्तानगंज पुलिस ने अपशब्द कहने और धमकाने के आरोप में सिंचाई विभाग सरयू नहर खंड 3 में तैनात एसडीओ शिव गोपाल शुक्ला सहित एक नामजद और दो अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के दुबौला चौकी क्षेत्र के भरवलिया गांव निवासी रत्नेश मिश्रा ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया।

जैकब बेथेल का शतक फिर भी ऑस्ट्रेलिया मजबूत

सिडनी। जैकब बेथेल के पहले टेस्ट शतक ने सिडनी टेस्ट को पांचवें दिन तक खींच दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब भी एशेज सीरीज को 4-1 से जीतने की मजबूत स्थिति में है। इंग्लैंड की उम्मीदें बेथेल की ऐतिहासिक पारी और सिमन मेंडबाजों पर टिकी हैं, जबकि स्टोक्स की चोट चिंता का विषय बनी हुई है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) पर खेला जा रहा एशेज 2026 का पांचवां और आखिरी टेस्ट मुकाबला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल के शानदार पहले टेस्ट शतक के बावजूद ऑस्ट्रेलिया सीरीज को 4-1 से जीतने की मजबूत स्थिति में है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 302/8 रन बना लिए थे और उसे 119 रनों की बढ़त हासिल हो चुकी है। अब मुकाबले का नतीजा पांचवें दिन तय होगा। जैकब बेथेल का यादगार शतक 22 वर्षीय जैकब बेथेल के लिए यह पारी किसी सपने से कम नहीं रही।

एसआईआर पर योगी की सख्ती, मंत्रियों को दी चेतावनी, खुद जिलों में उतकर छूटे नाम जुड़वाने का दिया आदेश

लखनऊ (संवाददाता)। मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची (एसआईआर) से जुड़े कार्यों को लेकर मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्रों के नाम हटाने के कार्य में लापरवाही बरती गई तो इसका सबसे अधिक नुकसान स्वयं मंत्रियों और सरकार को उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियाद है और इसमें किसी भी प्रकार की चूक स्वीकार्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर स्वयं

निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि फाइलों और बैठकों से बाहर निकलकर जमीनी स्तर पर काम किया जाए। मंत्रियों को आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया को तेज करने के साथ-साथ छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम अनिवार्य रूप से जुड़वाने का लक्ष्य दिया गया है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि किसी भी दशा में पात्र मतदाता छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने मंत्रियों को चेताते हुए कहा कि यदि वे ढीले पड़े तो इसका राजनीतिक और प्रशासनिक खामियाजा उन्हें ही भुगतना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूची पर जितनी मेहनत आज की जाएगी, उतना ही आगे का रास्ता आसान होगा। निष्पक्ष, शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची से न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी, बल्कि जनविश्वास भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि क्षेत्र में रहकर निगरानी करना केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। हर मंत्री को यह सुनिश्चित करना होगा कि बूथ स्तर तक सही जानकारी पहुंचे और कार्यकर्ता सक्रिय रहें। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि मंत्रियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें और समयबद्ध तरीके से सभी आपत्तियों का निस्तारण करें।

यूपी में फ्यूचर रेडी तहसीलों का निर्माण, थमेगा भ्रष्टाचार

लखनऊ (संवाददाता)। प्रदेश सरकार राजस्व प्रशासन को अत्याधुनिक, डिजिटल और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में फ्यूचर रेडी तहसीलों का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य तहसील स्तर पर नागरिकों को तेज, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी और तकनीक-आधारित राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना है। फ्यूचर रेडी तहसीलें उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासनिक क्रांति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं, जो नागरिक-केंद्रित शासन को मजबूत करने के साथ राज्य के समग्र विकास को नई रफ्तार देंगी। इन तहसीलों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-फाइलिंग सिस्टम, ऑनलाइन रिकॉर्ड मैनेजमेंट और स्मार्ट वर्कस्पेस जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए सभी तहसीलों का सर्वे और विस्तृत फ्रेमवर्क तैयार करने का कार्य चल रहा है, जिसे जून 2026 तक पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। भूमि अभिलेख, नामांतरण, प्रमाण-पत्र जारी करना, विवाद निपटारा और अन्य राजस्व सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन की जाएंगी। नागरिकों को बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। राजस्व प्रशासन के डिजिटलाइजेशन से प्रदेश की ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

लखनऊ में पारंपरिक पसंदीदा व्यंजनों के साथ आधुनिक क्यूजीन ने भी अपनी जगह बनाई

लखनऊ (संवाददाता)। लखनऊ की खाने की पसंद में पारंपरिक और नए जमाने के स्वादों का शानदार मेल देखने को मिला। क्लासिक नाश्तों से लेकर भरपेट डिनर और देर रात की तलब तक, पारंपरिक पसंदीदा व्यंजनों के साथ आधुनिक क्यूजीन ने भी अपनी जगह बनाई। ह्यहाऊ इंडिया स्विगीह्न के लखनऊ एडिशन, जो शहर की बदलती फूड हैबिट्स की एक झलक और बीते साल का स्वादिष्ट रीकैप पेश की है। इन रुझानों पर बात करते हुए, स्विगी फूड मार्केटप्लेस के चीफ बिजनेस ऑफिसर सिद्धार्थ भाकू ने कहा 2025 में खाना हमारे रोजमर्रा के जीवन और जश्न का अहम हिस्सा बना रहा और भारत ने अपने पसंदीदा व्यंजनों का आनंद लिया। लखनऊ शहर में हमने पारंपरिक स्वाद और राष्ट्रीय पसंद के बीच बेहतरीन संतुलन देखा। देर रात की भूख से लेकर प्रीमियम डाइनिंग आउट तक, लखनऊ ने खाने के जरिए अपनी सांस्कृतिक विविधता को अपनाया। खाना एक भावना है, और हम शहर के हर कोने में, हर भोजन, हर जश्न के साथ, बेहतरीन फूड अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 2025 में चिकन बिरयानी लखनऊ का सबसे ज्यादा ऑर्डर किया जाने वाला व्यंजन रहा, लगभग 5.5 लाख ऑर्डर के साथ इसने अपनी बादशाहत कायम रखी। इसके बाद पनीर ग्रेवी और तीसरे स्थान पर पनीर पिज्जा रहा। मिठाइयों में देसी क्लासिक्स की धूम रही। बूंदी लड्डू औसतन रोज 176 से अधिक बार ऑर्डर होकर चार्ट में सबसे आगे रहा, इसके बाद गुलाब जामुन और काजू बर्फी रहे। शहर की सुबहें जानी-पहचानी पसंद के साथ शुरू हुईं। वेज कचौड़ी ने नाश्ते के ऑर्डर में औसतन रोज करीब 240 ऑर्डर के साथ बढ़त दर्ज की, इसके बाद वेज बन्स और वेज वड़ा रहे। आलू पराठा और प्याज कचौड़ी जैसे अन्य पसंदीदा व्यंजनों को भी सालभर अच्छी मांग मिली। दोपहर (3 बजे से शाम 7 बजे) स्नैक टाइम में 1 लाख से ज्यादा ऑर्डर के साथ वेज बर्गर छाए रहे, जबकि पनीर पिज्जा दूसरा सबसे पसंदीदा स्नैक बना। डिनर लखनऊ का सबसे पसंदीदा समय बनकर उभरा, जहां डिनर ऑर्डर में साल-दर-साल 15प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। देर रात खाने का चलन भी धीरे-धीरे शहर में लाइफस्टाइल बनता जा रहा है, जहां रात 12 बजे से 2 बजे के बीच ऑर्डर में 25.6प्रतिशत की सालाना बढ़त देखी गई। दिन की शुरूआत शाकाहारी क्लासिक्स से होती थी तो देर रात की क्रेविंग कुछ अलग ही कहानी बयां की, जहां पनीर पिज्जा सबसे आगे रहा, इसके बाद वेज बर्गर और चिकन बर्गर रहे। खाने का प्यार किसी सीमा में बंधा नहीं रहा, कर्नाटक क्यूजीन 42प्रतिशत सालाना वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली क्यूजीन बनी, इसके बाद 36प्रतिशत के साथ बंगाली क्यूजीन रही। महाराष्ट्रीयन क्यूजीन को 1.63 लाख ऑर्डर मिले और आंध्र क्यूजीन ने 1.4 लाख ऑर्डर दर्ज किए, जो देशभर के स्वादों के प्रति शहर की बढ़ती रुचि को दशार्ता है। चलते-फिरते खाने का चलन भी खूब बढ़ा, जहां लखनऊ जंक्शन पर फूड ऑन ट्रेन ऑर्डर में सालभर में 200प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। किफायती खाने के विकल्पों को शहर में खूब पसंद किया गया। स्विगी के 99 स्टोर पर पिज्जा टॉप सेलिंग में शामिल रहा, जहां पनीर पिज्जा औसतन रोज करीब 213 बार ऑर्डर किया गया। वेज पिज्जा और कॉर्न पिज्जा भी वेज बर्गर के साथ टॉप 5 ऑर्डर किए जाने वाले व्यंजनों में शामिल रहे। दफ्तरों में, खाने ने लंबे कामकाजी दिनों और टीम सेलिब्रेशन को ऊर्जा दी। डेस्कईट्स पर मैकआलू टिक्की बर्गर औसतन रोज 242 ऑर्डर के साथ सबसे ज्यादा मंगाया गया।

राइफल क्लब मैदान की नीलामी रोकने की मांग,सदर विधायक ने सीएम को लिखा पत्र

लखनऊ/बांदा (संवाददाता)। बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बांदा शहर में स्थित प्राचीन राइफल क्लब खेल मैदान की नीलामी रोकने की मांग की है। बांदा विकास प्राधिकरण द्वारा इस मैदान की नीलामी की जा रही है, जिसके लिए पत्रांक 933६ बां०वि० प्रा०६2025-26 के तहत 1 जनवरी 2026 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। नीलामी की तिथि 21 जनवरी 2026 निर्धारित है। विधायक द्विवेदी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि यह राइफल क्लब खेल मैदान विधानसभा क्षेत्र बांदा सदर का एकमात्र बचा हुआ खेल मैदान है। इस ऐतिहासिक मैदान पर मेजर ध्यानचंद, सुरेश रैना, पीयूष चावला, प्रवीण कुमार और आर.पी. सिंह जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी खेल चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह खेल मैदान वर्ष 1902 में तत्कालीन जमींदार द्वारा पुलिस परेड और खेल के उपयोग के लिए लीज पर दिया गया था। पुलिस लाइन का निर्माण होने के बाद से इसका उपयोग मुख्य रूप से खिलाड़ियों द्वारा किया जा रहा है। यह मैदान बांदा का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ लगातार खेल प्रतियोगिताएं, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। पूरे बांदा नगर में यह एकमात्र ऐसा मैदान है जो खेल और अन्य सामाजिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध है। इसकी नीलामी की सूचना से नगरवासियों में चिंता व्याप्त है।

यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, 20 आईपीएस का हुआ तबादला

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। जिसके तहत 20 आईपीएस के तबादले किए है। लखनऊ कमिश्नरेट से अमित वर्मा का हटा कर अपर्णा को संयुक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया है। शासन द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार प्रयागराज जोन के अपर पुलिस महानिदेशक को हटाया गया है, जबकि लखनऊ पुलिस आयुक्तालय के भी अधिकारियों के तबादले किये गये हैं। सूत्रों के अनुसार लखनऊ आयुक्तालय के संयुक्त पुलिस आयुक्त अमित वर्मा को उनके पद से हटाकर नयी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी किरण एस को लखनऊ रेंज का पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। पीटीएस जालौन में लंबे समय से तैनात ज्योति नारायण को प्रयागराज जोन का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। इसके साथ ही विजय ढुल को प्रयागराज पुलिस आयुक्तालय में अपर पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। जारी आदेश के तहत रामकुमार को अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक्स, राजकुमार को अपर पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार तथा डॉ. संजीव गुप्ता को अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ बनाया गया है। प्रशांत कुमार को एडीजी प्रशासन और तरुण गाबा को एडीजी सुरक्षा, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इसके अलावा आशुतोष कुमार को एडीजी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, अपर्णा कुमार को संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ तथा राजेश मोदक को आईजी स्थापना, लखनऊ नियुक्त किया गया है। आर.के. भारद्वाज को आईजी रेलवे, लखनऊ और आनंद कुलकर्णी को आईजी एंटी करप्शन, लखनऊ बनाया गया है। एन. कोलांची को आईजी रेलवे, प्रयागराज नियुक्त किया गया है। वहीं, राजीव मल्होत्रा को आईजी यूपी एसएफआईएस, लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। तबादला आदेश के तहत रोहन पी. कनय को डीआईजी विशेष जांच, लखनऊ, मोहम्मद इमरान को डीआईजी भवन एवं कल्याण, लखनऊ, संतोष कुमार मिश्र को डीआईजी पीटीएस, जालौन तथा विजय ढुल को अपर पुलिस आयुक्त, प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया है ।यह फेरबदल प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

यूपी कैबिनेट विस्तार का पहला चहरा तय, योगी सरकार में सपा की बागी विधायक पूजा पाल बनेंगी मंत्री

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले कुछ दिनों से कवायद काफी तेज हो गई है। पिछले दिनों सीएम योगी की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही सुगबुगाहट को और अधिक मजबूती मिली है। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें एक ऐसा नाम है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। ये नाम सपा की बागी विधायक पूजा पाल का है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पूजा पाल को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। यूपी के कौशांबी जिले की चायल विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर विधायक पूजा पाल को सीएम योगी की तारीफ करने की वजह से पार्टी से निकाला गया है। उन्होंने अतीक अहमद और अशरफ गैंग के खिलाफ योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि इस सरकार में उन्हें इंसाफ मिला। इतना ही नहीं पूजा पाल ने अतीक अहमद के साम्राज्य के अंत का जिक्र विधानसभा में भी करते हुए सीएम योगी को धनयवाद बोला था। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी। जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। बता दें कि अतीक अहमद ने पूजा पाल के पति और बसपा विधायक राजू पाल की हत्या करवाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पूजा पाल को भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करते देखा गया था। इतना ही नहीं वे अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स से भी भाजपा नेताओं की तस्वीरें साझा करती रहती हैं। सीएम योगी ने भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूजा पाल का जिक्र करते हुए सपा पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने तंजात्मक अंदाज में कहा था, श्माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कैसे की जाती है वो आप अपने ही पार्टी की विधायक पूजा पाल से पूछ सकते हैं। आपकी सरकार थी लेकिन आपने उन्हें न्याय नहीं दिया। बेटी चाहे इस पक्ष की हो या फिर सत्ता पक्ष की यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे न्याय मिले। पूजा पाल के मंत्री बनने की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि वे सपा के पीडीए फामूर्ला का हिस्सा हैं। दलित समाज से आने वाली पूजा पाल को मंत्री बनाकर बीजेपी समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉमूर्ले पर सवाल उठाना चाहती है।

भाजपा सरकार मनरेगा को खत्म करने की गोपनीय साजिश बना रही

लखनऊ (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने की कोशिश इस प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना को धीरे-धीरे खत्म करने की एक गोपनीय साजिश रची गयी है। गौरतलब है कि पिछले संसदीय सत्र में पारित नया कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण (वीबी-जीरामजी) अधिनियम, 2025, मनरेगा की जगह ले रहा है। इस नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है। इसका ध्यान बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों के निर्माण पर है, जिसमें तकनीक का उपयोग, मजदूरी के लिए केंद्र-राज्य के बीच 60/40 का नया वित्तीय अनुपात, पारदर्शिता (बायोमेट्रिक,जियो-टैगिंग) और पीएम गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों से ग्रामीण कार्यों को जोड़ने का प्रावधान है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा एक सरकारी योजना थी, जो ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के अकुशल मजदूरी कार्य की कानूनी गारंटी देती थी। इसका उद्देश्य आजीविका सुरक्षा बढ़ाना और सड़कों, तालाबों और जल संरक्षण संरचनाओं जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना था। यह न्यूनतम मजदूरी, पुरुष-महिला को समान वेतन और 15 दिनों के भीतर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित करती थी। यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान पोस्ट करते हुए कहा कि मनरेगा का नाम बदलने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि यह भाजपा की उस मंशा को दशार्ता है जिसके तहत इस योजना को गुपचुप तरीके से खत्म करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा, ष्मनरेगा का नाम बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। असल में यह मनरेगा को धीरे-धीरे खत्म करने की भाजपा की गुप्त साजिश है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कई तरीकों से इस योजना को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा, एक तरफ भाजपा सरकार लगातार मनरेगा का बजट घटा रही है, दूसरी तरफ उसने राज्यों पर ऐसा वित्तीय दबाव बना दिया है कि केंद्र से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे में देरी और कमी के कारण पहले से खाली खजाने वाले राज्य यह सोचने को मजबूर हैं कि अतिरिक्त धन कहां से लाएं। यादव ने दावा किया कि इससे राज्य अंततः इस योजना को सीमित करने या छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। सपा अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने सैकड़ों ग्राम सभाओं को शहरी श्रेणी में डालकर मनरेगा को एक और झटका दिया है, जिससे वे ग्रामीण रोजगार निधि से वंचित हो गई हैं। उन्होंने कहा, कई ग्राम सभाओं को शहरी श्रेणी में डालकर भाजपा सरकार ने उनका मनरेगा बजट भी छीन लिया है। यादव ने कहा, भाजपा का असली लक्ष्य सिर्फ मनरेगा का नाम बदलना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह राम-राम कह देना है। भाजपा की प्राथमिकताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने जोड़ा, भाजपा अपने अलावा किसी और का पेट भरते देख नहीं सकती। विपक्षी दल लंबे समय से केंद्र पर मनरेगा के लिए अपर्याप्त बजट आवंटन और मजदूरी भुगतान में देरी के आरोप लगाते रहे हैं, हालांकि सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है और कहती है कि आवंटन मांग-आधारित है तथा आवश्यकता के अनुसार धन जारी किया जाता है। इस मुद्दे को गरीबों के अधिकारों से जुड़ी बड़ी लड़ाई बताते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा, ष्आज के गरीबों को भाजपा की जरूरत नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि आगामी चुनावों से पहले मनरेगा और कल्याणकारी खर्च विपक्ष के हमलों का प्रमुख मुद्दा बने रहेंगे।

पूर्वांचल के कूर्मियो में वर्चस्व की जंग

लखनऊ (संवाददाता)। सरदार सेना के अध्यक्ष डॉ. आरएस पटेल ने जबसे जनहित संकल्प पार्टी का गठन किया है, यूपी के पूर्वांचल के कूर्मियो में वर्चस्व की जंग तेज हो गई है। कुर्मी समाज का दल कहे जाने वाले अपनादल एस में भी बेचैनी है। यह बेचैनी ज्यादा इसलिए है कि कुर्मी वोटों के लिए भाजपा धीरे-धीरे करके अपना दल एस से निर्भरता कम करने का प्रयास कर रही है। स्वतंत्रदेव सिंह के फेल होने के बाद केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रोजेक्ट किया है। पंकज चौधरी के बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बदल रहे सियासी समीकरण। अपना दल एस का बेस वोट कुर्मी है। मिजार्पुर बनारस जौनपुर प्रयागराज प्रतापगढ़ फतेहपुर सहित कुछ अन्य कुर्मी बाहुल्य जिलों में भी मजबूती है। सत्ता के लिए भाजपा को अपना दल एस और अपना दल एस को भाजपा की जरूरत है। इन दोनों दलों के बीच गठबंधन 2014 से कायम है। भाजपा ने झटका देने का प्रयास किया जरूर, लेकिन जब खिसकती जमीन दिखी तो आंखें खुलीं।अपना दल एस पर से निर्भरता खत्म करने के लिए भाजपा ने पहले स्वतंत्रदेव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। स्वतंत्रदेव सिंह मूलरूप से पूर्वांचल के मिजार्पुर के हैं। लेकिन वह अपने को कुर्मी नेता के रूप में प्रतिस्थापित करने में नाकामयाब रहे। टार्गे था पूर्वांचल से अपना दल एस का प्रभाव कम कर अपना बढ़ाये लेकिन सफल नहीं हो सके। यही टार्गेट संभवतः नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को भी मिला होगा ।लखनऊ से बाहर उनका दौरा आठ जनवरी को मिजार्पुर होने जा रहा है। वह पूर्व मंत्री और चुनार के पूर्व विधायक कद्दावर नेता रहे ओमप्रकाश सिंह से भी मिलने उनके गांव मगरहा जाने वाले हैं। चर्चा है मकर संक्रांति के बाद योगी मंत्रिमंडल के होने वाले विस्तार में अनुराग सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। इससे मिजार्पुर और बनारस दोनों में अपना दल एस पर प्रभाव पड़ना तय है। अनुराग सिंह की मां स्व. सरोज सिंह बनारस की मेयर रही हैं।अनुराग सिंह का घर भी सीखड़ ब्लॉक के मगरहा गांव में है। उनका बनारस के कुर्मी बाहुल्य विधानसभाओं में आना-जाना रहता है। अनुराग सिंह को मंत्री बना दिया जाता है तो मिजार्पुर में सत्ता के दो केंद्र हो जाएंगे। इसमेंअनुराग मजबूत हो सकते हैं। अनुप्रिया पटेल और अनुराग सिंह में 2014 से ही 36 का रिश्ता है ।मिजार्पुर संसदीय सीट को सामान्य बनाने में अनुराग सिंह ने ही मेहनत की, यह कहना गलत नहीं होगा। तैयारी थी उन्हें भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ने की लेकिन ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अपना दल से हो गया और बनारस से मोदी की जीत पक्की होने लिए मिजार्पुर संसदीय सीट अपना दल एस के कोटे में चली गई। तभी से अनुप्रिया पटेल लगातार चुनाव जीत रही हैं। सांसद न बन पाने की कसक अनुराग सिंह के मन में है, उनके पिता ओमप्रकाश सिंह भी भूले नहीं हैं। प्रदेश में कुर्मी जाति के लोगों पर जहां भी अत्याचार हो रहा है,वहाँ जनहित संकल्प पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। न्याय के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। पूर्वांचल में कुर्मी समाज का रुझान तेजी से इस ओर बढ़ा है। अपना दल एस इसके प्रभाव को कम करना चाहता है, भाजपा भी। नुकसान से बचने के लिए भाजपा और अपना दल एस दोनों मंथन में जुटे हैं। आगामी विस्तार में अपना दल एस अपनी पार्टी से एक और मंत्री चाहता है। ज्यादा संभावना है कि वह पूर्वी उत्तर प्रदेश का और कुर्मी विधायक ही होगा।

संक्षिप्त खबरें

जाम से परेशान जनता पूछ रही सवाल कब स्थानान्तरित होगा चारबाग का बस अड्डा

लखनऊ (संवाददाता)। चारबाग बस टर्मिनल को नवीन मूर्तरूप प्रदान करने के लिए कार्य शुरू हो चुका है और गतिपूर्वक चल रहा है। जिसके लिए बस अड्डे के निकास द्वार को पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। जिसके कारण तथा विभागीय अव्यवस्था के चलते वहां हर समय जाम की भीषण स्थिति बनी रहती है। पीक आवर में तो स्थिति बद से बदतर हो जाती है। मात्र दो सौ मीटर की दूरी को पार करने में एक घंटे से अधिक का समय लग रहा है। बस अड्डे के पूरे तरह से शिफ्ट न होने के कारण यहां यात्रियों के लगातार पहुंचने के कारण प्रवेश द्वार से ही बसों का आवागमन चालू रखा गया है। इसके बाद तमाम रोडवेज की बसों के साथ डग्गामार वैन और कारें भी सड़क पर ही खड़ी रहती है। जो विभागीय अधिकारियों पुलिस प्रशासन के अलावा अन्य सभी को आसानी से दिखायी देती है। जिसकी वजह से सड़क पर आसपास का यातायात पूर्णरूप से बाधित होने लगता है। चारबाग के जाम के चलते लोग चारबाग से मेंट्रो पकड़ने बजाय दुगार्पुरी से ही मेट्रो पकड़ना अधिक पसंद कर रहें है। बस अड्डे के आसपास यातायात को सुचारु रूप को संचालित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ नाका थाने की पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। चारबाग बस अड्डा चालू होने की वजह से ऑटो, टेम्पो व ई-रिक्शा वालों के बीच यात्रियों को बैठाने की होड लगी रहती है जो भीषण जाम लगने का एक और कारण बन रहा है। रोज-रोज के जाम के झाम से परेशान राजधानीवासी अब सवाल पूछ रहे है कि आखिर कब तक चारबाग का बस अड्डा आलमबाग स्थानान्तरित होगा? कब चारबाग के इस भीषण जाम से कुछ राहत मिलेगी? ताकि चारबाग क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कम हो सके।

31 जनवरी तक संपत्ति घोषित न करने पर रुकेगा वेतन और प्रमोशन

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के करीब 14 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। शासन के नए आदेश के अनुसार, सभी श्रेणियों के कर्मियों को 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का पूरा विवरण अपलोड करना होगा। जो कर्मचारी आदेश की अनदेखी करेंगे, उन्हें न केवल आर्थिक नुकसान झेलना होगा बल्कि उनके करियर की प्रगति पर भी ब्रेक लग जाएगा। सरकार का मानना है कि लोक सेवकों द्वारा अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करना भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे पहले भी कई बार निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने पोर्टल पर डेटा अपडेट नहीं किया था। मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों को सख्त हिदायत दी है कि वे मातहतों से समय सीमा के भीतर डेटा फीडिंग सुनिश्चित कराएं, ताकि सरकारी कामकाज में जवाबदेही तय की जा सके। सरकार का रुख काफी सख्त है। 31 जनवरी की समय सीमा बीतने के बाद, पोर्टल पर विवरण न देने वाले कर्मचारियों का फरवरी माह का वेतन जारी नहीं किया जायेगा। ऐसे कर्मचारियों को विभाग में मिलने वाली किसी भी पदोन्नति या भविष्य के लाभों के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। शासन ने साफ कर दिया है कि बिना संपत्ति के विवरण के एसीआर को अधूरा माना जाएगा।कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करके दो तरह के विवरण देने होंगे। चल संपत्ति के अंतर्गत उन्हें अपने बैंक बैलेंस, गहने, वाहन और अन्य निवेशों की जानकारी देनी होगी, जबकि अचल संपत्ति में जमीन, मकान, प्लॉट या किसी भी प्रकार की व्यावसायिक संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य है ।यह विवरण न केवल कर्मचारी के नाम पर बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद संपत्ति के लिए भी लागू होगा। तकनीकी बाधा दूर करने के लिए एनआईसी और आईटी विभाग को पोर्टल अपडेट रखने के निर्देश दिए गए हैं। नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारियों को डेटा फीड करने में कोई समस्या न आए। सर्वर की समस्याओं से बचने के लिए कर्मचारियों को जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

भगवान गलती करें तो कहां जाये लोग ?

लखनऊ (संवाददाता)। लोग डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते हैं ।उन्हें भरोसा होता है कि एक वही हैं जो उनकी जान बचा सकते हैं लेकिन जब डॉक्टर ही मरीज की जान से खिलवाड़ करने लगे तो उसे क्या कहिएगा ।यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज के साथ ऑपरेशन के दौरान बड़ी लापरवाही हुई। लखनऊ के एरा अस्पताल में डॉक्टर्स सर्जरी के वक्त मरीज के पेट में ही सर्जिकल औजार भूल गए। डॉक्टर्स की ये लापरवाही स्वास्थ्य सेवाओं पर कई सवाल खड़े कर रही है। ये मामला बाहर आया कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अस्पताल के 13 डॉक्टर्स और दो मालिकों के खिलाफ एफआईआरदर्ज की। पीड़िता रूपा शर्मा ने इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने जो कहानी बताई वो सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गये। रूपा शर्मा नामक महिला का एरा अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। कुछ दिनों बाद ठीक होने की बजाय उनके पेट में दर्द और परेशानी बढ़ने लगी ।रूपा शर्मा ने हॉस्पिटल जाकर इस बात की शिकायत की लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी ।अस्पताल प्रशासन और सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। रूपा शर्मा अपने पेट के दर्द से बेहाल थीं। एरा अस्पताल में नजरअंदाज कर दिया तो वो जांच करवाने के लिए दूसरे हॉस्पिटल पहुंची। पीड़िता की एक्स-रे रिपोर्ट देखकर अस्पताल के डॉक्टर हैरान रह गए। रिपोर्ट में पता चला कि उनके पेट में एक सर्जिकल औजार मौजूद है जिसके बाद अस्पताल वालों ने बिना देरी किए उनका ऑपरेशन किया और औजार को बाहर निकाला ।एरा हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से रूपा शर्मा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी शिकायत पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट ऑर्डर मिलते ही ठाकुरगंज पुलिस ने तुरंत एरा असप्ताल के 13 डॉक्टर्स और 2 मालिकों के खिलाफ एक्शन लिया ।पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शिक्षकों ने की समायोजन प्रक्रिया रद्द करने की मांग

बांदा/ लखनऊ (संवाददाता)। जनपद में शिक्षकों ने वर्तमान समायोजन प्रक्रिया (3.0) को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं, आरटीई अधिनियम के उल्लंघन और उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाया गया है। शिक्षकों का कहना है कि इस प्रक्रिया से उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। ज्ञापन में बताया गया है कि समायोजन प्रक्रिया में कनिष्ठ शिक्षकों का समायोजन किया गया है। यह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कनिष्ठ शिक्षकों के समायोजन पर रोक लगाने के पूर्व के फैसले का सीधा उल्लंघन है। कनिष्ठ शिक्षकों के चयन में भी गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं। कहीं जनपद स्तर पर नियुक्ति को आधार माना गया, तो कहीं विद्यालय में ठहराव को। कुछ मामलों में वरिष्ठ शिक्षकों को समायोजित कर दिया गया, जबकि कुछ अन्य में न वरिष्ठता देखी गई और न ही कनिष्ठता, बल्कि मध्य के शिक्षकों का समायोजन कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, कुछ विद्यालयों में एक ही विषय के दो शिक्षक होने के बावजूद, एक विषय वाले शिक्षक को हटा दिया गया। वहीं, मार्च 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को भी शासनादेश के विरुद्ध सुदूरस्थ विद्यालयों में समायोजित कर दिया गया है। जारी किए गए समायोजन आदेशों में कई शिक्षकों को उनके वर्तमान विद्यालय के पास का विद्यालय आवंटित न करके जानबूझकर दूर के विद्यालय दिए गए। जबकि कुछ विशेष लोगों को अनुचित लाभ देते हुए जिला मुख्यालय के अधिक नजदीक के विद्यालयों में समायोजित कर दिया गया।

सम्पादकीय

पंजाब में बढ़ते अपराध

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि पंजाब में सरेआम की जा रही लक्षित हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुस्साहसी हत्यारे अपने मंसूबों को अंजाम देकर साफ निकल जाते हैं। यह विडंबना ही है कि पंजाब में नये साल की शुरूआत दिनदहाड़े हुई हत्याओं की एक श्रृंखला के साथ हुई है। अब चाहे लुधियाना जिले में एक पूर्व कबड्डी खिलाड़ी की निर्मम हत्या हो या अमृतसर के मैरिज रिसॉर्ट में एक विधायक के करीबी सरपंच की गोली मारकर बेरहमी से हत्या, इनसे पता चलता है कि पंजाब के अपराधियों में कानून का भय नहीं रह गया। निश्चित रूप से ये घटनाएं पंजाब में गंभीर चुनौती बनती एक जटिल समस्या की ओर इशारा करती हैं। इस चिंताजनक होती स्थिति की वजह लगातार अपराधी गिरोहों के नेटवर्क का मजबूत होना, घातक हथियारों की सहज उपलब्धता और पुलिस बल पर लगातार बढ़ता दबाव भी है। दूसरी ओर विपक्षी दल आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला चलाए रहते हैं और राजनीतिक लक्ष्यों के लिये मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग करते रहते हैं। वहीं सरकार इस संकट को अपने पूर्ववर्तियों द्वारा विरासत में छोड़ा गया बताते हैं। लेकिन एक हकीकत है कि इन बयानबाजियों से नागरिकों की असुरक्षा कम नहीं होती है। वहीं पंजाब के शीर्ष पुलिस अधिकारियों की दलील होती है कि पंजाब में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। लेकिन राज्य में बढ़ते अपराधों के संकट को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से जब हत्याएं राज्य के भीड़भाड़ वाले इलाकों में होती हैं तो लोगों का कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। वहीं दूसरी ओर राज्य के पुलिस महानिदेशक की दलील है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ड्रोन के जरिये हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थ भेजकर सीमांत राज्य पंजाब के खिलाफ परोक्ष युद्ध छेड़े हुए है। निश्चय ही यह बात इस सीमावर्ती राज्य के लिये गंभीर चिंता का विषय है। इसमें दो राय नहीं कि पंजाब के डीजीपी का पाक से अपराधियों को प्रश्रय देने वाला बयान चिंता बढ़ाने वाला है। खासकर उस राज्य के लिये, जिसने एक दशक तक उग्रवाद का सामना किया हो। लेकिन पंजाब के अपराध संकट के लिये केवल बाहरी कारकों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह पुलिस विभाग की शिथिलता व खुफिया तंत्र की नाकामी के साथ सामाजिक विद्रूपताओं से भी उपजा संकट है। निस्संदेह, राज्य में अधिक बेरोजगारी है। बंदूक संस्कृति का महिमामंडन भी गंभीर चुनौती है। वहीं दूसरी ओर युवाओं में रातों-रात धनवान बनने का लालच भी स्थानीय व क्षेत्रीय गिरोहों के पनपने की गंभीर वजह है। इसके अलावा पुलिस विभाग की संरचना की भी कुछ विसंगतियां सामने आती हैं। मसलन पुलिस व्यवस्था में उच्च अधिकारियों की तो अधिकता है मगर फील्ड स्टाफ पर काम का बोझ जरूरत से ज्यादा है। इसके अलावा पुलिस के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप के भी आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस, हासिल कुछ सफलताओं के बावजूद जनता का विश्वास जीतने के लिये संघर्ष कर रही है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजियों से इतर राज्य सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव लाकर धरातल पर गंभीर प्रयास करने होंगे। मौजूदा हालात में बहुआयामी रणनीति बनाने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। इसके अंतर्गत पुलिस सुधार भी प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की जरूरत है, ताकि हाइटैक अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके। इसके साथ ही अपराध नियंत्रण में केंद्रीय एजेंसियों से बेहतर तालमेल करने की भी जरूरत है। इसके अलावा बंदूकों पर लगाम लगाने के लिये कानून को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता होगी। राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कौशल विकास में व्यापक निवेश करने तथा भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा में लाने के प्रयास योजनाबद्ध ढंग से करने होंगे। ऐसे राज्य में जो एक दशक तक चरमपंथ की त्रासदी झेल चुका हो, अपराधियों के खिलाफ बड़ी मुहिम वक्त की मांग है। राज्य के सत्ताधीशों को चाहिए कि पंजाब द्वारा कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को गैंगस्टरों, ड्रग माफिया और आतंकवादियों के घातक गठजोड़ का शिकार कदापि नहीं होने दें।

सोमनाथ के शिखर पर फहराती ध्वजा गवाह है, आतंक अस्थाई है और आस्था शाश्वत

महमूद गजनवी ने सोचा था कि उसने सोमनाथ का अंत कर दिया। वह बेवकूफ था। वह भूल गया था कि सोमनाथ का अर्थ है सोम (चंद्रमा) का नाथ। चंद्रमा घटता है, पर मरता नहीं है। इतिहास सिर्फ धूल भरी तिथियों का ढेर नहीं होता, यह उन जख्मों का लेखा-जोखा है, जो सभ्यताओं के चरित्र को तय करते हैं। आज जब हम वर्ष 2026 में सोमनाथ की दहलीज पर खड़े हैं तो समुद्र की लहरों में सिर्फ भक्ति का स्वर नहीं है, बल्कि एक हजार साल पुराना वह चीत्कार भी कहीं दबा हुआ है। जनवरी 1026 में जब महमूद गजनवी के घोड़ों की टापों ने प्रभास पाटन की पवित्र मिट्टी को रौंदा था, तब वह सिर्फ एक मंदिर की लूट नहीं थी। वह हमारी सामर्थ्य, हमारी एकता और हमारे आत्म-गौरव पर किया गया एक ऐसा प्रहार था, जिसका दाग धोने में हमें दस सदियां लग गईं। आज गजनवी इतिहास के कूड़ेदान में एक क्रूर आक्रांता के रूप में दर्ज है और सोमनाथ का शिखर बादलों को चूम रहा है, लेकिन इस भव्यता के बीच खुद से एक कड़वा सवाल पूछना जरूरी है, क्या हम वाकई बदल गए हैं या हम आज भी सिर्फ इतिहास के दोहराव का इंतजार कर रहे हैं? 10वीं-11वीं शताब्दी का भारत सोने की चिड़िया तो था, लेकिन वह चिड़िया अलग-अलग पिंजरों में बंद थी। हम टुकड़ों में बंटे थे, हम सामरिक रूप से अपाहिज थे। गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और हर बार वह हमारी आपसी फूट की दरारों से रास्ता बनाकर अंदर घुसा। सबसे बड़ा दर्द यह नहीं कि उसने मंदिर तोड़ा, बल्कि यह है कि जब 50 हजार निहत्थे श्रद्धालु अपनी देह की दीवार बनाकर मंदिर बचा रहे थे, तब भारत के शक्तिशाली राजा अपनी सीमाओं के भीतर दुबके बैठे थे। गजनवी शिवलिंग को खंडित करके और अकूत संपदा ऊंटों पर लादकर ले गया, लेकिन उससे बड़ा बोझ वो हमारे मानस पर पराजित मानसिकता का छोड़ गया था। विगत 1000 वर्षों में हमने पत्थर तो जोड़ लिए, लेकिन क्या हमने अपनी उन कमियों को सुधारा? गजनवी के समय कोई केंद्रीय सुरक्षा नहीं थी। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम परमाणु शक्ति हैं, हमारी सेनाएं विश्व में श्रेष्ठ हैं और खैबर दर्रे से अब किसी लुटेरे का आना नामुमकिन है, लेकिन आज का गजनवी दर्रों से नहीं, बल्कि डिजिटल नैरेटिव, वैचारिक कट्टरपंथ और आंतरिक फूट के रास्तों से घर के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा है। आज भी जब बामियान में बुद्ध तोड़े जाते हैं या मध्य-पूर्व में प्राचीन विरासतें मलबे में तब्दील की जाती हैं तो यह अहसास होता है कि गजनवी मरा नहीं है, वह सिर्फ अपनी खाल बदलकर हमारे सामने खड़ा है। सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। स्वतंत्र भारत में जब सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, तब भी कुछ बुद्धिजीवियों के पेट में दर्द हुआ था। नवंबर 1947 में प्रभास पाटन के तट पर खड़े होकर सरदार पटेल ने कहा था कि यह अपमान को मिटाने का कार्य है। लेकिन, दुःखद यह है कि आजादी के बाद भी दशकों तक हमें अपनी ही विरासत के लिए अदालतों और दलीलों का सहारा लेना पड़ा। आज जब हम राम मंदिर या काशी विश्वनाथ का कायाकल्प देखते हैं तो यह केवल ईंट-पत्थर का जुड़ना नहीं है, बल्कि उस सांस्कृतिक संप्रभुता की वापसी है, जिसे गजनवी जैसे लोग कुचलना चाहते थे। एक और चुभता हुआ सवाल, हमने कभी प्रतिशोध नहीं लिया, यह हमारी महानता है या हमारी कमजोरी? हमने अपने मंदिर बनाए, लेकिन किसी की इबादतगाह नहीं उजाड़ी। हमने वसुधैव कुटुंबकम को जिया, लेकिन क्या दुनिया ने हमारी इस उदारता का सम्मान किया? सोमनाथ का इतिहास चीख-चीख कर कहता है कि शांति केवल शक्ति के साये में ही पल सकती है। अगर आप सशक्त नहीं हैं तो आपका सत्य भी मलबे में दबा दिया जाएगा। भारत की कहानी भी सोमनाथ जैसी ही है महमूद गजनवी ने सोचा था कि उसने सोमनाथ का अंत कर दिया। वह बेवकूफ था। वह भूल गया था कि सोमनाथ का अर्थ है सोम (चंद्रमा) का नाथ। चंद्रमा घटता है, पर मरता नहीं है। वह फिर से पूर्ण होता है। भारत की कहानी भी सोमनाथ जैसी ही है। हमने अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा ली है, हमने अपनी राजनीतिक पहचान ढूंढ ली है और हमने अपने मंदिरों को फिर से गगनचुंबी बना लिया है।

हम टुकड़ों में बंटे थे, हम सामरिक रूप से अपाहिज थे। गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और हर बार वह हमारी आपसी फूट की दरारों से रास्ता बनाकर अंदर घुसा। सबसे बड़ा दर्द यह नहीं कि उसने मंदिर तोड़ा, बल्कि यह है कि जब 50 हजार निहत्थे श्रद्धालु अपनी देह की दीवार बनाकर मंदिर बचा रहे थे, तब भारत के शक्तिशाली राजा अपनी सीमाओं के भीतर दुबके बैठे थे। गजनवी शिवलिंग को खंडित करके और अकूत संपदा ऊंटों पर लादकर ले गया, लेकिन उससे बड़ा बोझ वो हमारे मानस पर पराजित मानसिकता का छोड़ गया था। विगत 1000 वर्षों में हमने पत्थर तो जोड़ लिए, लेकिन क्या हमने अपनी उन कमियों को सुधारा? गजनवी के समय कोई केंद्रीय सुरक्षा नहीं थी। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम परमाणु शक्ति हैं, हमारी सेनाएं विश्व में श्रेष्ठ हैं और खैबर दर्रे से अब किसी लुटेरे का आना नामुमकिन है, लेकिन आज का गजनवी दर्रों से नहीं, बल्कि डिजिटल नैरेटिव, वैचारिक कट्टरपंथ और आंतरिक फूट के रास्तों से घर के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा है। आज भी जब बामियान में बुद्ध तोड़े जाते हैं या मध्य-पूर्व में प्राचीन विरासतें मलबे में तब्दील की जाती हैं तो यह अहसास होता है कि गजनवी मरा नहीं है, वह सिर्फ अपनी खाल बदलकर हमारे सामने खड़ा है। सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। स्वतंत्र भारत में जब सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, तब भी कुछ बुद्धिजीवियों के पेट में दर्द हुआ था। नवंबर 1947 में प्रभास पाटन के तट पर खड़े होकर सरदार पटेल ने कहा था कि यह अपमान को मिटाने का कार्य है। लेकिन, दुःखद यह है कि आजादी के बाद भी दशकों तक हमें अपनी ही विरासत के लिए अदालतों और दलीलों का सहारा लेना पड़ा। आज जब हम राम मंदिर या काशी विश्वनाथ का कायाकल्प देखते हैं तो यह केवल ईंट-पत्थर का जुड़ना नहीं है, बल्कि उस सांस्कृतिक संप्रभुता की वापसी है, जिसे गजनवी जैसे लोग कुचलना चाहते थे। एक और चुभता हुआ सवाल, हमने कभी प्रतिशोध नहीं लिया, यह हमारी महानता है या हमारी कमजोरी? हमने अपने मंदिर बनाए, लेकिन किसी की इबादतगाह नहीं उजाड़ी। हमने वसुधैव कुटुंबकम को जिया, लेकिन क्या दुनिया ने हमारी इस उदारता का सम्मान किया? सोमनाथ का इतिहास चीख-चीख कर कहता है कि शांति केवल शक्ति के साये में ही पल सकती है। अगर आप सशक्त नहीं हैं तो आपका सत्य भी मलबे में दबा दिया जाएगा। भारत की कहानी भी सोमनाथ जैसी ही है महमूद गजनवी ने सोचा था कि उसने सोमनाथ का अंत कर दिया। वह बेवकूफ था। वह भूल गया था कि सोमनाथ का अर्थ है सोम (चंद्रमा) का नाथ। चंद्रमा घटता है, पर मरता नहीं है। वह फिर से पूर्ण होता है।

फिर निशाने पर जेएनयू

देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर एक बार फिर दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हमलावर हैं। इस संस्थान को टुकड़े-टुकड़े गैंग का अड्डा बताया जा रहा है। मोदी सरकार के आने के बाद से जेएनयू भाजपा और संघ समर्थकों के निशाने पर रहता आया है। खासकर संस्थान के जो छात्र वामपंथी विचारों के हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके से देशद्रोही ठहराने की कोशिशें की जाती हैं। वही कोशिशें सोमवार से फिर शुरू हो चुकी हैं।दरअसल सोमवार 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों में आरोपी बनाए गए उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि अन्य पांच सह आरोपियों को जमानत दे दी गई है। जबकि छह साल पहले 2020 में जेएनयू के इतिहास की सबसे बड़ी हिंसक घटना 5 जनवरी को हुई थी। जिसमें विवि परिसर में नकाबपोश लोगों की भीड़ ने हॉस्टलों में घुसकर छात्रों पर लाठी, पत्थर और लोहे की रॉड से हमला किया था। इस हमले में तत्कालीन छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष सहित कम से कम 28 लोग घायल हुए थे, इसमें दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे थे कि आखिर उसके रहते इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। आज तक उस घटना के असल दोषियों को सजा नहीं हुई है। इसी पर हर साल जेएनयू में छात्र इकत्रत्र होकर अपने गुस्से का इजहार करते हैं। सोमवार रात भी छात्र एकत्र हुए और जेएनयू परिसर में नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हुई। इसमें उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल की भी खबरें हैं। यह सही है कि किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में कट्टर से कट्टर विरोधी के लिए भी मयार्दा के दायरे में रहकर शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन फिर यह संतुलन दोनों पक्षों से अपेक्षित होता है।अभी केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कुछ लोगों ने जेएनयू को श्टुकड़े-टुकड़ेश गिरोह का अड्डा बना दिया है। राहुल गांधी, टीएमसी, कम्युनिस्ट जैसे लोग इस गिरोह का हिस्सा हैं... ये लोग सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं रखते। उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में और प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। पाकिस्तान जैसी मानसिकता रखने वालों को भारत की जनता ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।सरकार के विरोध में जब भी कोई आवाज शैक्षणिक परिसरों से उठती है, उसे दबाने या फिर गलत साबित करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। जेएनयू में तो अब होली-दीवाली जैसे मौकों पर भी खान-पान के नाम पर ही झड़पें होने लगी हैं। एक बार तो विजयादशमी पर एबीवीपी ने रावण दहन में अफजल गुरु, उमर खालिद और शरजील इमाम के चित्र लगाकर पुतला जलाए, जिस पर वामपंथी समूहों ने इसे इस्लामोफोबिया और नफरत फैलाने का आरोप लगाया। ऐसी तमाम झड़पों और हिंसक घटनाओं के पीछे मकसद यही है कि किसी भी तरह विश्वविद्यालय परिसर को हिंदुत्ववादी गतिविधियों का अड्डा बनाया जाए।सोमवार के विरोध के बाद ही एबीवीपी ने कहा है कि वह इस विरोध प्रदर्शन की शिकायत पुलिस में करेगा। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा है कि छात्र 5 जनवरी, 2020 को परिसर में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए हर साल विरोध प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने बताया, विरोध प्रदर्शन में लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे और किसी पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं है। वे किसी को लक्षित करते हुए नहीं थे। बता दें कि जेएनयू में वामपंथी समर्थित छात्र संगठन का कब्जा है और यह भी संघ और भाजपा के लिए एक बड़ी कसक है कि उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद जेएनयू में वाममोर्चा पस्त नहीं हो रहा है।जेएनयू में सोमवार रात लगे नारों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि आप लोगों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का एक तरीका होता है। वहीं राजद सांसद मनोज झा ने पूछा है कि क्या यह चुनिंदा आक्रोश है? हां, लोग स्वाभाविक रूप से गुस्से में हैं। हममें से कई लोगों को भी लगता था कि शरजील और उमर को जमानत मिल जानी चाहिए थी। पांच साल से अधिक समय बीत चुका है और मुकदमे के नाम पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यह अपने आप में चिंता का विषय है- संवैधानिक सुरक्षा लागू होने से पहले किसी को कितने समय तक जेल में रहना चाहिए? यह एक तरह से आपराधिक न्याय प्रणाली पर भी चोट है। बता दें कि शीर्ष अदालत के सोमवार के फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं, हालांकि कानून के जानकार अधिकतर लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं कि पांच साल से ज्यादा वक्त तक बिना मुकदमा जेल में रखना क्या मूल अधिकारों का हनन नहीं है। क्योंकि अदालत ने ही जेल को अपवाद और बेल को नियम कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उमर खालिद और शारजील इमाम की जमानत याचिकाएं अभियोजन द्वारा पेश संरक्षित गवाहों की परीक्षा पूरी होने या इस आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर (जो पहले हो) विचार की जा सकती हैं। इसके बाद दोनों आवेदक जमानत के लिए फिर आवेदन कर सकते हैं। इस आदेश पर भी जानकार सवाल उठा रहे हैं कि जब छह सालों में गवाहों की जांच पूरी नहीं हुई तो क्या एक साल में पूरी हो जाएगी।

पैर फैला रही पूंजीवादी व फासीवादी ताकतें

मंगत राम पासला

बंगलादेश में सांप्रदायिक तत्वों द्वारा वहां के धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर किए जा रहे हिंसक हमले और भीड़ द्वारा धार्मिक स्थलों की बेअदबी करना हर पहलू से निंदनीय और बेहद चिंताजनक घटनाक्रम है। धार्मिक अल्पसंख्यक आबादी पर कातिलाना हमलों का यह घिनौना सिलसिला अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कई अन्य देशों में भी देखा गया है। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों के भीतर कुछ सिरफिरे अंधाधुंध गोलियां चलाकर बेगुनाहों की लाशों के ढेर लगा देते हैं। दक्षिणपंथी-पिछड़ी सोच वाले ये कातिल गिरोह अक्सर धर्म-जाति, रंग-नस्ल, प्रवास या क्षेत्रीय मुद्दों को आधार बनाकर अपने उक्त कुकर्मों को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। भारत के भीतर भी प्रतिक्रियावादी दुंत्विवादी संगठनों (बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आदि) के अराजकतावादी कार्यकर्त्ता और इनके द्वारा पाले गए पेशेवर अपराधी तत्व मुस्लिम और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं और प्रगतिशील लोगों को हिंसक हमलों का निशाना बनाते हैं। अपने इन अमानवीय कार्यों को उचित ठहराने के लिए अशांति के इन दूतों ने देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी को धार्मिक अल्पसंख्यकों (मुसलमानों, ईसाइयों आदि) से फर्जी खतरे का एक काल्पनिक विमर्श (नैरेटिव) गढ़ा हुआ है। पिछले लगभग 11 साल से आर.एस.एस. की सोच और दिशा के अनुसार राज-काज चला रही भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने इन्हें पूरी सरपरस्ती बख्शी हुई है। पिछले दिनों ईसाइयों के पवित्र त्यौहार क्रिसमस के अवसर पर बजरंग दल और कई अन्य अराजकतावादी संगठनों के हुड़दंगियों ने बेखौफ होकर वहशियाना ढंग से धार्मिक आयोजनों के लिए तैयार किए गए पंडाल तोड़े और ईसा मसीह की मूर्तियां खंडित कीं। गंगा स्नान करने गए विदेशियों के सिरों से क्रिसमस की झलक देने वाली टोपियों का उतारा जाना और सरङ्कहद में श्री गुरु गोदिं सिंह जी के दो छोटे साहिबजादों की याद में मनाए जाने वाले शहीदी जोड़ मेले में निहंग बाणा पहने कम उम्र के 2 बच्चों द्वारा लोगों के सिरों पर पहनी गई टोपियों को जबरन उतारना और नेजों पर टांग कर भद्दी किस्म की संकीर्णता का प्रदर्शन किया जाना, विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के भीतर जोर पकड़ रही सांप्रदायिक सोच और कट्टरता को दर्शाता है। 2008 से अमरीका से शुरू हुई पूंजीवादी आघ्थक मंदी, जिसने दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, ने पूरी दुनिया की राजनीति में घमासान मचा रखा है। इस महामंदी की अभिव्यक्ति बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, तालाबंदी, छंटनी, वित्तीय लेनदेन में बार-बार पैदा हो रही अस्थिरता आदि के रूप में देखी जा सकती है। विभिन्न देशों की पूंजीवादी सरकारें, वहां के कॉर्पोरेट घरानों और बहुराष्ट्रीय निगमों के असीमित मुनाफे में और वृद्धि करने में लगी हुई हैं। दूसरी ओर, संकट की सबसे अधिक मार झेल रहे श्रमिक वर्गों को कोई राहत देने की बजाय उन पर टैक्स आदि का बोझ और अधिक लादा जा रहा है, सुविधाओं और सबसिडी में निरंतर कटौती की जा रही है। पूंजीवादी व्यवस्था में पनपे इस आघ्थक संकट ने दुनिया के अनेक देशों में तानाशाह प्रवृत्तियों वाली दक्षिणपंथी और फासीवादी ताकतों को अपने पैर पसारने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बलि का बकरा बनाने के लिए बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया है। अमरीका, भारत, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अर्जेंटीना आदि देशों में दक्षिणपंथी सरकारों का अस्तित्व में आना इस तथ्य की पुष्टि करता है। इन सरकारों द्वारा मेहनतकश वर्गों को मिलने वाली मामूली आघ्थक सुविधाएं, कानूनी अधिकार और सामाजिक सुरक्षा वापस लेकर इन वर्गों को गरीबी के जंजाल में फंसाकर गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। इन कदमों के विरोध में दुनिया के विकसित पूंजीवादी देशों फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमरीका, स्पेन, इंगलैंड, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया आदि के लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं और लंबी हड़तालें हुई हैं। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भी यही आर्थिक नीतियां लागू की जा रही हैं, जो मजदूर वर्ग के लंबे संघर्षों और भारी कुर्बानियों के फलस्वरूप हासिल किए गए अधिकारों और रियायतों पर प्रहार करती हैं। मोदी सरकार द्वारा क्रांतिकारी कानूनों में से एक गिने जाने वाले मनरेगा को खत्म करके रोजगार गारंटी से पूरी तरह भागने वाला नया वीबी जी राम जी कानून लाना अत्यंत गरीब लोगों के साथ एक भद्दा मजाक है। इस बात का संतोष है कि दुनिया के श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा अपने कड़वे अनुभवों से सीखकर पूंजीवादी ढांचे की बेरहम लूट से मुक्ति के लिए समाजवादी व्यवस्था के निर्माण की अनिवार्य आवश्यकता को अनुभव करने लगा है। अमरीका, जहां कम्युनिस्ट और समाजवाद शब्दों को कभी बहुत बड़ा हौव्वा बना दिया गया था, वहां भी अब मजदूर-किसान और युवा हाथों में समाजवाद के बैनर और लाल झंडे लिए सड़कों पर जोरदार नारे लगाते अक्सर देखे जा सकते हैं। नए साल के भीतर हम भी प्रयास करें कि भारत भी इस कार्य में पीछे न रहे।

रिपब्लिकन्स क्यों छोड़ रहे हैं कांग्रेस

चार्ली हंट

कांग्रेस के मध्यावधि चुनाव नवम्बर तक नहीं होंगे लेकिन पहले ही रिकॉर्ड संख्या में सदस्यों ने चुनाव न लडने का इरादा घोषित कर दिया है- सदन में कुल 43, साथ ही 10 सीनेटर। शायद सबसे चर्चित व्यक्ति, जॉर्जिया की रिपब्लिकन प्रतिनिधि माजोर्री टेलर ग्रीन ने नवम्बर में न केवल सेवानिवृत्त होने का, बल्कि 5 जनवरी को कांग्रेस से पूरी तरह से इस्तीफा देने का इरादा घोषित किया, अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूरे एक साल पहले। इस राजनीतिक उथल-पुथल के पीछे कई कारण हैं, जिनमें गतिरोध से उत्पन्न निराशा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की निराशाजनक लोकप्रियता रेटिंग शामिल हैं, जो चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। डैमोक्रेट्स के पक्ष में संभावित ब्लू वेव से प्रभावित होने या संभवतरू सत्ता में बने रहने के लिए आवश्यक अथक प्रयासों से भयभीत होने की बजाय, कई रिपब्लिकन्स ने लहर के चरम पर पहुंचने से पहले ही अपने घर लौटने का फैसला कर लिया है। अब तक, 2 दर्जन रिपब्लिकन प्रतिनिधि सभा सदस्यों ने या तो सदन से इस्तीफा दे दिया है या 2026 में पुनरू चुनाव न लडने की घोषणा कर दी है। हाऊस रिपब्लिकन कॉकस के भीतर भी बढ़ती चिंता है कि ग्रीन की घोषणा एक चेतावनी है और इसके बाद कई इस्तीफे होंगे। एक राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में, जो कांग्रेस और राजनेताओं की पुनरू चुनाव रणनीतियों का अध्ययन करता है, मुझे कई हाऊस सदस्यों को रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक कठिन मध्यावधि चुनाव से पहले पद छोड़ते हुए देखकर आश्चर्य नहीं होता। फिर भी, चुनाव न लडने वाले लोगों की भारी संख्या हमें वाशिंगटन के प्रति व्यापक असंतोष के बारे में कुछ बताती है। कई नियोजित प्रस्थान वास्तव में सेवानिवृत्ति हैं, जिनमें अधिक उम्र के और अधिक अनुभवी सदस्य शामिल हैं। उदाहरण के लिए, 78 वर्षीय डैमोक्रेटिक कांग्रेसी जेरी नैडलर 34 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो

रहे हैं, नवोदित चुनौती देने वालों के बढ़ते दबाव और डैमोक्रेट्स के बीच बढ़ती सहमति के बाद कि अब पुराने राजनेताओं के लिए पद छोडने का समय आ गया है। पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी, जो मार्च में 86 वर्ष की हो जाएंगी, भी सेवानिवृत्त हो रही हैं। कई बार, कांग्रेस सदस्य उन्हीं कारणों से पद छोड़ते हैं जिनके कारण अन्य कर्मचारी कोई भी नौकरी छोड़ते हैं। कई अमरीकियों की तरह, कांग्रेस सदस्यों को कहीं और अधिक आकर्षक अवसर मिल सकते हैं। सेवानिवृत्त सदस्य लॉगिं फर्मों और निगमों के लिए आकर्षक उम्मीदवार होते हैं, क्योंकि उनके पास संस्था के भीतर की जानकारी और संपर्क होते हैं। अन्य सदस्य चुनावी पद के लिए महत्वाकांक्षी बने रहते हैं और कांग्रेस में अपने पद का उपयोग किसी अन्य पद के लिए एक सीढ़ी के रूप में करने का निर्णय लेते हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्य नियमित रूप से सीनेट सीट के लिए चुनाव लडने हेतु सेवानिवृत्त होते हैं, जैसे कि इस बार मिशिगन की डैमोक्रेटिक सांसद हेली स्टीवंस। अन्य सदस्य राज्यपाल सहित कार्यकारी पदों के लिए चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि दक्षिण कैरोलिना की रिपब्लिकन सांसद नैन्सी मेस। लेकिन कुछ सदस्य काम से बढ़ती निराशा और कार्यों को पूरा करने में असमर्थता के कारण कांग्रेस छोड़ रहे हैं। इसके अलावा, इस वर्ष कई राज्यों में मध्य-दशक के पुनघ्वतरण प्रक्रिया के साथ सीमाओं में हुए बदलावों ने सांसदों की प्राथमिकताओं को अस्त-व्यस्त कर दिया है। अपरिचित निर्वाचन क्षेत्र मौजूदा सांसदों को समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने के लिए विवश कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनके स्थापित निर्वाचन क्षेत्रों से उनका संबंध टूट जाता है। टैक्सास में, 6 रिपब्लिकन और 3 डैमोक्रेट (राज्य के पूरे प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधिमंडल का लगभग एक चौथाई) या तो सेवानिवृत्त हो रहे हैं या अन्य पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका आंशिक कारण 2026 के लिए राज्य का नया निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन है। निचले सदन में रिपब्लिकन बहुमत पहले से ही बहुत कम है, इसलिए इसका नीतिगत नीतियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। नवम्बर में होने वाले मध्यावधि चुनावों का परिणाम कुछ भी हो, वाशिंगटन में इन सदस्यों के इस्तीफे का स्पष्ट रूप से महत्व है और ये कांग्रेस में व्याप्त अराजकता के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं।

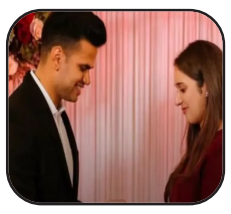

जल्द शादी के बंधन में बंध सकते हैं अर्जुन और सानिया

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर जल्द ही मंगेतर सानिया चंदोक से शादी रचा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों इस साल मार्च में शादी के बंधन में बंध सकते हैं। महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबकि, अर्जुन मंगेतर सानिया चंदोक से मार्च में शादी रचा सकते हैं। बता दें कि, दोनों की पिछले साल अगस्त में सगाई हुई थी। सानिया मुंबई के प्रसिद्ध व्यवसायी रवि घई की पोती हैं। घई परिवार हॉस्पिटेलिटी और खाद्य क्षेत्र में सुप्रसिद्ध है, जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और आइसक्रीम ब्रांड ब्रुकलिन क्रीमरी का स्वामित्व है। सचिन ने की थी सगाई की पुष्टि अर्जुन और सानिया की सगाई एक निजी कार्यक्रम में हुई थी, जिसकी जानकारी शुरूआत में मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई थी।

मैं विवाह करूंगी...श्रद्धा कपूर ने अपनी शादी को लेकर किया ऐलान! फैंस हुए एक्साइटेड

एक बार फिर श्रद्धा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में

बॉलीवुड गलियारों में काफी समय से एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी के अफेयर की खबरें सुनने को मिलती रही हैं। हालांकि, दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। वहीं, अब एक बार फिर श्रद्धा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ डेटिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बात उनकी शादी तक पहुंच गई है। दरअसल, हाल ही में श्रद्धा कपूर अपने ज्वेलरी ब्रांड को इंस्टाग्राम पर प्रमोट कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें वह वैलेंटाइन डे और ब्रेकअप पर हल्के-फुल्के अंदाज में बात करती नजर आईं। वीडियो में श्रद्धा ने कहा कि वैलेंटाइन डे के आसपास सबसे ज्यादा ब्रेकअप होते हैं और बजट खत्म होने की वजह से लोग महंगे गिफ्ट नहीं खरीद पाते, इसलिए उन्होंने खास वैलेंटाइन डे गिफ्ट तैयार किए हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक फैन ने उनसे सवाल कर लिया कि वह शादी कब करेंगी। आमतौर पर ऐसे सवालों से बचने वाली कई एक्ट्रेसेस के उलट, श्रद्धा ने इस सवाल का बेहद दिलचस्प और मजेदार जवाब दिया। उन्होंने लिखा, मैं करूंगी, ये विवाह करूंगी। बस फिर क्या था, श्रद्धा का यह जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। श्रद्धा के इस जवाब के बाद फैंस और ज्यादा एक्साइटड हो गए। किसी ने उनसे शादी का प्रस्ताव रख दिया तो किसी ने लिखा कि अब ज्यादा इंतजार मत करवाइए। एक यूजर ने कमेंट किया, मेरे साथ कर लो शादी, तो दूसरे ने लिखा, वो दिन कब आएगा, प्यारी स्त्री ?ह्व वहीं कुछ फैंस ने तो सीधे-सीधे उन्हें जल्दी दुल्हन बनने की सलाह दे डाली। बता दें, श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी के रिलेशनशिप की अफवाहें तब तेज हुई थीं, जब साल 2024 में दोनों को मुंबई में एक साथ डिनर डेट पर देखा गया था। इसके बाद से ही दोनों के अफेयर की खबरें लगातार सामने आने लगीं। हालांकि, श्रद्धा ने अब तक अपने और राहुल के रिश्ते पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। बताते चले राहुल मोदी पेशे से एक लेखक हैं और उन्होंने प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी सफल फिल्मों की कहानी और पटकथा लिखी है। इंडस्ट्री में उनका नाम एक टैलेंटेड राइटर के तौर पर जाना जाता है। श्रद्धा कपूर के शादी को लेकर दिए गए जवाब ने उनके फैंस की उम्मीदें जरूर बढ़ा दी हैं। हालांकि, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मजेदार जवाब सिर्फ हंसी-मजाक था या वाकई आने वाले समय में श्रद्धा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई बड़ा ऐलान करने वाली हैं।

हैप्पी पटेल के पीछे की कहानी, जानें विर दास ने कैसे किया आमिर खान को कन्विंस

वीर दास ने आमिर खान के साथ अपने अनुभव पर खुलकर बात की है। अपनी आने वाली डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म हैप्पी पटेलरू खतरनाक जासूस को लेकर वीर दास ने बताया कि जब

कोई सुपरस्टार किसी प्रोजेक्ट पर सच्चे दिल से भरोसा करता है, तो वह उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ आगे बढ़ाता है। वीर दास ने कहा कि आमिर खान से मिलना उनके लिए थोड़ा डराने वाला अनुभव था, क्योंकि वह इंडस्ट्री में जिस ऊँचे मुकाम पर हैं, वहां तक पहुँचना आसान नहीं होता। उन्होंने बताया, वह इतने बड़े स्तर पर हैं कि आप उनसे सामान्य बातचीत करने में भी झिझकते हैं। मैंने करीब 10 साल तक आमिर सर से बात नहीं की थी। फिर एक दिन मैंने उन्हें मैसेज किया और पूछा, आमिर सर, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हां, अभी कॉल करो। फोन उठाते ही ऐसा लगा जैसे हम सालों से नियमित बात कर रहे हों।ह्व वीर दास ने यह भी साझा किया कि उन्होंने आमिर खान के सामने कितनी स्पष्टता से अपनी फिल्म का आइडिया रखा। उन्होंने कहा, मैंने उनसे साफ कहा कि मेरे पास एक फिल्म है और मैं चाहता हूं कि आप ही इसे बनाएं। अगर आप नहीं बनाएंगे, तो शायद कोई और भी नहीं बनाएगा।ह्व इस पर आमिर खान ने बिना देर किए उन्हें अगले हफ्ते नैरेशन देने के लिए बुला लिया। वीर ने बताया कि उन्होंने अब तक कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं देखा, जो इतनी सहजता से और इतनी जल्दी मिलने का समय दे। पहली नैरेशन के बाद कुल नौ बार स्क्रिप्ट पर चर्चा हुई। आमिर खान की सबसे बड़ी प्राथमिकता हमेशा कहानी और स्क्रिप्ट ही रही। नौ नैरेशन के बाद उन्होंने वीर से कहा, थोड़े पैसे लो और फिल्म के पांच सीन शूट करके दिखाओ।ह्व टेस्ट शूट देखने के बाद आमिर ने फिल्म को हरी झंडी दे दी। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हैप्पी पटेलः खतरनाक जासूस को वीर दास ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में मोना सिंह, शरीब हाशमी और मिथिला पालकर अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

दूसरे बेटे के जन्म के 20 दिन बाद ही सेट पर लौटीं भारती सिंह

पैपराजी को दिया खास सरप्राइज

भारती सिंह लगभग बीस दिन पहले ही दूसरे बेटे को जन्म दिया है। लेकिन करियर ब्रेक लेने की बजाय वह वापस काम पर लौट आई हैं। भारती सिंह रियलिटी शो लाफ्टर शेफ 3 के सेट पर काफी खुश दिखीं। कॉमेडियन भारती सिंह जब प्रेग्नेंट थीं तो भी वह लाफ्टर शेफ 3 को होस्ट कर रही थीं। हाल ही में उन्होंने दूसरे बेटे को जन्म दिया। बुधवार को भारती सिंह फिर से लाफ्टर शेफ 3 के सेट पर दिखीं। उन्होंने पैपराजी को भी एक खास सरप्राइज दिया।

भारती ने पैपराजी के साथ खूब मस्ती-मजाक भी किया, उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। कॉमेडियन भारती सिंह के कई वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें उन्हें लाफ्टर शेफ 3 रियलिटी शो के सेट पर देखा गया। प्रेग्नेंसी के दौरान भी वह इस शो को होस्ट कर रही थीं। इस शो के सेट पर ही उनको लेबर पेन हुआ और वह हॉस्पिटल में एडमिट हुईं। 19 दिसंबर 2025 को भारती सिंह ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। लेकिन बेटे के जन्म के बाद ब्रेक लेने की बजाय भारती शूटिंग के सेट पर लौट आईं। वह लाफ्टर शेफ 3 के सेट पर पैपराजी से मजाक करती दिखीं। पैपराजी ने भी उन्हें मां बनने की बधाई दी। भारती ने सेट पर बांटी मिठाई भारती सिंह का एक और वीडियो वायरल है, जिसमें वह पैपराजी को मिठाई बांट रही हैं। अपने बेटे के जन्म की खुशियों उनके साथ बांट रही हैं। भारती सिंह सिर्फ रियलिटी शो को होस्ट ही नहीं कर रही हैं, वह यूट्यूब पर व्लॉग बनाकर भी पोस्ट करती हैं, अपने लाइफस्टाइल को फैंस के साथ शेयर करती हैं।

फिर लौट रही है सुपरहिट जोड़ी

आनंद एल राय और धनुष की भव्य प्रेम गाथा की तैयारी

फिल्म इंडस्ट्री में आनंद एल राय और धनुष की एक और बड़ी रीयूनियन को लेकर चचाएँ तेज हो गई हैं। तेरे इश्क में की जबरदस्त सफलता के बाद, इंडस्ट्री के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक यह क्रिएटिव जोड़ी एक बड़े पैमाने पर बनी पीरियड एक्शन रोमांटिक फिल्म पर विचार कर रही है, जिसे एक भव्य कैनवास पर माउंट किया जाएगा। रांझणा से लेकर अतरंगी रे और अब तेरे इश्क में तक, आनंद एल राय और धनुष ने एक ऐसी साझेदारी बनाई है जो भावनात्मक जोखिम और मजबूत किरदारों पर आधारित कहानी कहने के लिए जानी जाती है। इन फिल्मों ने न सिर्फ धनुष की हिंदी फिल्म यात्रा को एक खास पहचान दी है, बल्कि आनंद एल राय को भी ऐसे फिल्ममेकर के तौर पर स्थापित किया है जो अपने कलाकारों से गहरे और दमदार परफॉर्मेंस निकलवाते हैं। इसी के साथ, बतौर निर्देशक और निमार्ताकृ अपने बैनर के तहत नए और अलग किस्म के कंटेंट को सपोर्ट करते हुएकृ आनंद एल राय की इंडस्ट्री में मौजूदगी लगातार मजबूत हुई है। हालिया सफलताओं ने यह साफ कर दिया है कि वे बड़े स्केल पर सोचते हुए भी कहानी की भावनात्मक गहराई से समझौता नहीं करते। ऐसे में एक पीरियड एपिक उनके करियर का अगला स्वाभाविक (और साहसिक) कदम माना जा रहा है। वहीं धनुष, जिनकी फिल्म चॉइस हमेशा मास अपील और आर्टिस्टिक क्रेडिबिलिटी के बीच संतुलन बनाती है, उनके लिए पीरियड एक्शन रोमांस एक

बिल्कुल नई सिनेमाई दुनिया खोल सकता है। अपनी तीव्र शारीरिक मौजूदगी और भावनात्मक रेंज के लिए पहचाने जाने वाले धनुष का इतिहास, संघर्ष और जुनून से भरी कहानी में उतरना किसी बदलाव से ज्यादा, एक बड़ा विस्तार लगता है। हालांकि फिलहाल प्रोजेक्ट को लेकर सारी जानकारियाँ बेहद गोपनीय रखी गई हैं और कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह फिल्म उनकी क्रिएटिव पार्टनरशिप को एक नए स्तर पर ले जाएगी। उद्देश्य यही बताया जा रहा है कि भावनाओं और भव्यता का संतुलन बनाया जाएकृजहाँ आनंद एल राय की सिग्नेचर स्टोरीटेलिंग बनी रहे और साथ ही बड़े पैमाने की सिनेमाई भव्यता भी देखने को मिले। और हवा दे रही है। अगर यह प्रोजेक्ट कन्फर्म होता है, तो यह डेवलपमेंट में मौजूद सबसे हाई-प्रोफाइल फिल्मों में से एक बन सकता हैकृऔर हिंदी सिनेमा पर अपनी गहरी छाप छोड़ चुकी इस जोड़ी के लिए एक नए अध्याय की शुरूआत साबित हो सकता है।

रणवीर सिंह ने रचा इतिहास, एक भाषा में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

एक ऐसे उद्योग में जहां सफलता को आँकड़ों से मापा जाता है, कुछ ही पल ऐसे होते हैं जब ये आँकड़े इतिहास बन जाते हैं। धुरंधर के साथ रणवीर सिंह ने ऐसा ही एक ऐतिहासिक पल रचा है, जब उन्होंने एक ही भाषा हिंदी कृ में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का नेतृत्व किया। यह उपलब्धि सिर्फ अपने विशाल पैमाने के कारण नहीं, बल्कि अपनी यात्रा के कारण भी खास है। धुरंधर ने किसी क्षणिक उछाल पर भरोसा नहीं किया,

बल्कि धीरे-धीरे मजबूत होती गई, अपनी पकड़ बनाए रखी और हफ्तों तक शानदार प्रदर्शन करती रही। फिल्म ने अपने पाँचवें मंगलवार (33वें दिन) को भारत में 831.40 करोड़ की नेट कमाई का आंकड़ा छू लिया, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नया मील का पत्थर है। इस असाधारण सफलता के केंद्र में रणवीर सिंह का दमदार अभिनय है। उन्होंने बड़े कैनवास पर रचे गए इस किरदार में नियंत्रण, गहराई और स्पष्टता के साथ जान फूंकी है। उनकी मौजूदगी संतुलित होते हुए भी बेहद प्रभावशाली है, जो कहानी को भव्यता और भावनाओं के साथ आगे बढ़ने देती है। यही संतुलन फिल्म को हर वर्ग के दर्शकों से जोड़ता है और इसकी रफ्तार को बनाए रखता है। ट्रेड विश्लेषकों और दर्शकों कृ दोनों कृ से फिल्म को भरपूर सराहना मिली है। इसकी लगातार मजबूत कमाई इस बात का प्रमाण है कि दर्शक रणवीर सिंह पर कितना भरोसा करते हैं। न सिर्फ एक सुपरस्टार के तौर पर, बल्कि एक ऐसे कलाकार के रूप में जो हर किरदार में ईमानदारी और मजबूती लाता है। दर्शक उनके निभाए किरदार और फिल्म के अनुभव, खासकर इसकी शानदार कहानी के लिए बार-बार सिनेमाघरों तक लौटे। आँकड़ों से परे, हम्जाह्व का किरदार एक सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। यह भूमिका आम बातचीत का हिस्सा बन गई है, जो दशार्ता है कि इसने दर्शकों पर कितना गहरा प्रभाव छोड़ा है। जब कोई किरदार पर्दे से निकलकर लोगों की जिंदगी में जगह बना ले, तो वह अभिनय की स्थायी छाप को दशार्ता है। धुरंधर के साथ रणवीर सिंह ने अपने करियर में एक निर्णायक अध्याय जोड़ दिया है। अब तक की सबसे बड़ी सिंगल-लैंग्वेज हिंदी फिल्म का नेतृत्व कर उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए एक नया मानदंड स्थापित किया है। यह पल समर्पण, कला और दर्शकों से गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। एक ऐसा कीर्तिमान जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।

बर्फ से ढकी पहाड़ियां, सर्दियों का खूबसूरत नजारा..करीना कपूर ने शेयर की वेकेशन फोटोज, विंटर लुक में किया सबको इम्प्रेस

एक्ट्रेस करीना कपूर खान बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत और शानदार हसीनाओं में से एक हैं, जो अपनी वर्क और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलती हैं। वह अपने बिजी शेड्यूल के बीच भी फैमिली संग मस्ती के पल एंजॉय करने से कभी नहीं चूकतीं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने नए साल का स्वागत बेहद स्टाइलिश और सुकून भरे अंदाज में किया। अपने न्यू ईयर और विंटर वेकेशन की खूबसूरत तस्वीरें बेबो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में बर्फ से ढकी पहाड़ियां, सर्दियों का खूबसूरत नजारा और शांत माहौल देखने को मिलता है। कुछ तस्वीरें आउटडोर हैं तो कुछ इनडोर, जो उनके वेकेशन के अलग-अलग पल दिखाती हैं। खास बात यह रही कि इन तस्वीरों में करीना कपूर के दोनों बेटे तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान (जेह) भी नजर आए, जिन्होंने पोस्ट को और भी खास बना दिया। एक तस्वीर में करीना रेस्टोरेंट टेबल पर बैठी नजर आ रही हैं, जहां वह चेहरे के सामने मास्क पकड़कर मस्ती भरे अंदाज में पोज दे रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में वह घर के अंदर एक आरामदायक फायरप्लेस के पास बैठी दिखती हैं, जहां सर्द मौसम में गर्माहट और सुकून का एहसास झलकता है। इसके अलावा उन्होंने अपने ठहरने की जगह से बर्फ से ढके घरों का नजारा भी दिखाया, जिसने फैंस को उनके शांत और खूबसूरत वेकेशन स्पॉट की झलक दी। करीना के इस फोटो डंप में उनके बेटे तैमूर और जेह भी खास आकर्षण बने। एक तस्वीर में तैमूर खुशी-खुशी खाना खाते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में वह अपना स्केटबोर्ड और हेलमेट पकड़े हुए किसी बिल्डिंग की ओर जाते दिखते हैं। वहीं जेह भी अपनी मां के साथ एक तस्वीर में नजर आए, जहां वह विंटर लुक में बेहद क्यूट लग रहे हैं। तीनों मां-बेटे विंटर आउटफिट्स में परफेक्ट फैमिली वेकेशन वाइब दे रहे हैं। करीना ने इस पोस्ट के लिए कोई लंबा कैप्शन नहीं लिखा, बल्कि सिर्फ एक ब्लू दिल और स्नोफ्लेक इमोजी के साथ तस्वीरें शेयर कीं। उनके इस पोस्ट पर आलिया भट्ट, सोनम कपूर, करिश्मा कपूर, अनन्या पांडे, सोनाक्षी सिन्हा समेत कई सेलेब्स और फैंस ने प्यार भरे रिएक्शन्स दिए। वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म दायरा की शूटिंग पूरी की है। यह एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन मेघना गुलजार कर रही हैं। फिल्म में करीना के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और फिलहाल पोस्ट-प्रोडक्शन फेज में है।

नौ चौके और 10 छक्के तीसरे यूथ वनडे में वैभव सूर्यवंशी का तूफान

बेनोनी। भारत अंडर-19 और दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 के बीच जारी तीन वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला बेनोनी में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज ने 200 से ज्यादा रनों की साझेदारी से भारत को अच्छी शुरूआत दिलाई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की अंडर-19 टीमों के बीच जारी तीन यूथ वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी कप्तान वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जमकर गरजा है। उन्होंने महज 63 गेंदों में शतक जड़कर विपक्षी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं। बेनोनी में खेले जा रहे इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है। आरोन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी की विशाल साझेदारी से भारत की अच्छी शुरूआत इस मुकाबले में ऑरोन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी ने टीम को शानदार शुरूआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 227 रनों की विशाल साझेदारी हुई। कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने महज 74 गेंदों में नौ चौके और 10 छक्के की सहायता से 127 रनों की धमाकेदार पारी खेली। वैभव के अलावा आरोन जॉर्ज ने भी तीसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन किया।

वेनेजुएला में कार्रवाई पर ट्रंप समर्थकों की राय बंटी

कोई खुश तो कोई भविष्य को लेकर आशंकित

वॉशिंगटन (एजेंसी)। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने कहा कि उनके समर्थक खुश हैं, लेकिन अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में एमएजीए वोटरों की राय पूरी तरह एक जैसी नहीं है। जानिए किसने समर्थन किया और कौन चिंतित दिखा... वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक साहसिक अमेरिकी सैन्य अभियान में गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क की जेल भेजे जाने के कुछ ही दिन बीते हैं। इस बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनके समर्थक इस कार्रवाई से बेहद खुश हैं। लेकिन अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों में एमएजीए (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन)) वोटरों से बात करने पर तस्वीर इतनी सीधी नहीं दिखती। डेट्रॉइट इलाके के ट्रंप समर्थक एरन टोबिन इसे किसी हॉलीवुड फिल्म की शुरूआत मानते हैं। उनका कहना है कि आने वाले वर्षों तक इस ऑपरेशन पर फिल्में बनेंगी। मैं रोमांचित हूं,ह्व उन्होंने कहा। ऐसे कई ट्रंप वोटर हैं जो फिलहाल इस कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि, यह ऑपरेशन ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप का समर्थन आधार पहले से ही जेफ्री एपस्टीन फाइल्स, बढ़ते हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर दबाव में है। ट्रंप ने चुनाव के दौरान अमेरिका फर्स्टह्व का नारा देते हुए विदेशी हस्तक्षेप से दूरी बनाने का वादा किया था, लेकिन वेनेजुएला में बिना कांग्रेस की मंजूरी सैन्य कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरूआती समर्थन, लेकिन बिना शर्त नहीं पेंसिल्वेनिया के बेंसलेम में ट्रंप मर्चेंडाइज स्टोर के बाहर मिले 67 वर्षीय पॉल बॉनर कहते हैं अभी तक मैं उनके साथ हूं। जब तक वह कोई बड़ी गलती नहीं करते। यह बयान बताता है कि समर्थन फिलहाल सशर्त है। ट्रंप के कुछ कट्टर समर्थक भी आशंकित हैं कि कहीं यह कदम अमेरिका को एक लंबे संघर्ष में न झोंक दे। खासकर तब, जब ट्रंप खुद नए युद्ध शुरू न करने का वादा कर चुके थे। मिसिसिपी से कोलोराडो तक बंटी राय उन्हें डर है कि कहीं अमेरिकी सैनिकों को युद्ध में न झोंक दिया जाए। वहीं, कोलोराडो के ट्रैविस गार्सिया इस कार्रवाई को सही ठहराते हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका ऐसे तानाशाहों पर कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। उनके अनुसार, इससे ट्रंप की छवि एक सख्त और फैसले लेने वाले नेता की बनती है। हालांकि, इसी राज्य में कुछ समर्थक यह भी मानते हैं कि अगर अमेरिका लंबे समय तक वेनेजुएला में उलझा रहा, तो समर्थन कमजोर पड़ सकता है। पेंसिल्वेनिया और मिडवेस्ट से भरोसा पेंसिल्वेनिया के रॉन सोटो को भरोसा है कि ट्रंप आगे की स्थिति संभाल लेंगे। उनका मानना है कि मादुरो एक बुरा शासक था और ट्रंप ने बाकी देशों में डर पैदा कर दिया है। इंडियाना के मार्क एडवर्ड मिलर कहते हैं कि उन्हें इस ऑपरेशन से हैरानी नहीं हुई।

ईरान में निर्वासित युवराज पहलवी ने की जनता से कार्रवाई की अपील

तेहरान (एजेंसी)। ईरान में महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ भड़के विरोध प्रदर्शनों में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच निर्वासित

युवराज रजा पहलवी ने ईरानी जनता से सड़कों पर उतरने की अपील की है। ईरान में बढ़ती महंगाई और गंभीर आर्थिक संकट के खिलाफ भड़के खामेनेई विरोधी प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, अब तक कम से कम 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। यह बीते तीन वर्षों में ईरान का सबसे बड़ा जन आंदोलन माना जा रहा है। मंगलवार को तेहरान के ऐतिहासिक बाजार में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। यह विरोध प्रदर्शन ईरानी रियाल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद और तेज हो गए, जिससे आम जनता की क्रय शक्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। निर्वासित युवराज रजा पहलवी की अपील ईरान के अंतिम शाह के पुत्र और निर्वासित युवराज रजा पहलवी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से ईरानी जनता से कार्रवाई का आह्वान किया है। उन्होंने संदेश में कहा 8 और 9 जनवरी को रात 8 बजे, जहां भी हों सड़कों पर या अपने घरों से एक साथ नारे लगाइए। आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर आगे की रणनीति घोषित की जाएगी। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में नारे और वीडियो वायरल हो रहे हैं। पश्चिमी ईरान के अबदानान शहर में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। वीडियो फुटेज में प्रदर्शनकारी जाविद शाह और पूरा शासन निशाने पर है जैसे नारे लगाते दिखे। कई जगहों पर खामेनेई का पतन होगा जैसे नारे भी सुनाई दिए। महंगाई से फूटा गुस्सा ईरानी मुद्रा हाल ही में 1 डॉलर के मुकाबले 14.7 लाख रियाल तक गिर गई। इससे व्यापारियों और आम नागरिकों में भारी आक्रोश फैल गया। 28 दिसंबर को तेहरान बाजार बंद होने के साथ ही विरोध की लहर शुरू हुई, जो जल्द ही पश्चिमी ईरान और कुर्द बहुल इलाकों तक फैल गई। दमन और विदेशी मिलिशिया की भूमिका रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरानी सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।

पॉक्सो के आरोपी को ठाणे की अदालत से मिली राहत

कहा- मामले में पर्याप्त सबूत नहीं

ठाणे (एजेंसी)। अदालत के फैसले में जोर दिया गया कि यौन इरादे का निर्धारण करना और न करना एक तथ्यात्मक प्रश्न है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोपित अपराधों के कानूनी तत्वों को स्थापित करने में विफल रहा। अदालत ने यह स्वीकार करते हुए कि पीड़िता उस समय नाबालिग थी, यह माना कि दोष सिद्ध करने के लिए सबूत अपर्याप्त थे। ठाणे की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की का पीछा करने और यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि उसके कृत्यों में यौन इरादा नजर नहीं आया, जो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण

(पॉक्सो) अधिनियम के तहत आवश्यक एक प्रमुख तत्व है। मजदूरी का काम करने वाले मयूरेश कैलाश शेल्के (25) आरोप है कि उसने 2019 में महाराष्ट्र के ठाणे शहर में 15 वर्षीय पीड़िता के घर में प्रवेश किया और उससे अपने प्यार का इजहार किया। 'पीड़िता के साथ नहीं हुआ शारीरिक संपर्क', कोर्ट की टिप्पणी न्यायाधीश रूबी यू मालवणकर ने टिप्पणी की कि पीड़िता के साथ कोई शारीरिक संपर्क नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि आरोपी की ओर से इस्तेमाल किए गए शब्द इस मामले के तथ्यों के हिसाब से किसी प्रकार के 'यौन इरादे' को प्रदर्शित करने वाले 'इरादे' के बराबर नहीं होंगे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, 'यौन इरादे में क्या शामिल है और क्या नहीं, यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है। इस मामले में आरोपी की ओर से प्रयुक्त शब्दों से ऐसा कोई यौन इरादा प्रतीत नहीं होता है।' 22 दिसंबर, 2025 को पारित हुए आदेश की प्रति मंगलवार को सामने आने के बाद ये जानकारी मिली। पीड़िता की ओर से इस मामले को लेकर 2019 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई गई थी। इसमें पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसका पड़ोसी शेल्के 1 नवंबर, 2019 को डोम्बिवली के म्हात्रे नगर स्थित एक चॉल में उसके घर में घुस गया, जब वह अकेले पढ़ाई कर रही थी। मामले में आरोपी के खिलाफ सबूत अपर्याप्त थे अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने पीड़िता से कहा, 'मुझे दादा कहकर मत पुकारो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आरोप लगाया गया कि वह उसका पीछा कर रहा था और बार-बार फोन कर रहा था। अभियोजन पक्ष ने शेल्के पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354डी (पीछा करना) और 441 (आपराधिक अतिक्रमण) के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 (यौन उत्पीड़न) और 11 (यौन शोषण) के तहत आरप लगाए। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील अमरीश एस जाधव ने अभियोजन पक्ष के मामले को चुनौती दी। अदालत ने बताया कि यह घटना कथित तौर पर घनी आबादी वाली चॉल में हुई थी, फिर भी किसी और स्वतंत्र गवाह का कोई अन्य सबूत पेश नहीं किया गया जो इस तरह के कृत्य को देखने के बारे में गवाही दे सकता था।

वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई पर अमेरिकी संसद से लेकर सड़क तक मतभेद

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिकी संसद में गंभीर मतभेद उभरते दिखे हैं। अमेरिकी संसद (कांग्रेस) में ट्रंप द्वारा सांसदों से परामर्श किए बिना इतना बड़ा कदम उठाने को एक नए युग के विस्तारवाद की शुरूआत माना जा रहा है। इस असंतोष को लेकर विदेश मंत्री मार्को रुबियो को सोमवार देर रात कांग्रेस नेताओं के सामने वेनेजुएला सैन्य अभियान की जानकारी पेश करनी पड़ी। उधर, इस कार्रवाई के विरुद्ध लोग सड़कों पर भी उतरे हैं।

अमेरिकी संसद में भी ट्रंप की कार्रवाई का विरोध अमेरिकी कांग्रेस का कहना है कि ट्रंप बिना परामर्श या कांग्रेस से अनुमति लिए अनुचित कदम उठा रहे हैं। इसी चिंता के बीच रिपब्लिकन नेता कैपिटल हिल (अमेरिकी संसद भवन) में बंद कमरे में हुई बैठक में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जबरन सत्ता से हटाने के ट्रंप के फैसले का समर्थन करते हुए दाखिल हुए, लेकिन कई डेमोक्रेट्स ने सवाल उठाया कि वेनेजुएला तट पर नौसैनिक बेड़ा तैनात है, जबकि देश के घाटे में चल रहे तेल उद्योग में पुनर्निवेश जरूरी है। उनका कहना है कि युद्ध शक्ति प्रस्ताव पर कांग्रेस की मंजूरी बिना वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई प्रतिबंधित है। अब सीनेट में इस सप्ताह इस मुद्दे पर चर्चा संभावित है। ट्रंप की कार्रवाई विदेश नीति के प्रति खतरनाक दृष्टिकोण : शूमर सीनेट के डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने चेताया कि वेनेजुएला में ट्रंप की कार्रवाई विदेश नीति के प्रति एक खतरनाक दृष्टिकोण की मात्र शुरूआत है।

वेस्ट बैंक को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी में इस्राइल, विवादित बस्ती के निर्माण का रास्ता साफ

तेल अवीव (एजेंसी)। इस्राइल के ई1 प्रोजेक्ट पर विवाद है क्योंकि यह यरुशलम के बाहरी इलाके से शुरू होकर कब्जे वाले वेस्ट बैंक के भीतरी हिस्से तक जाती है। आलोचकों का कहना है कि इससे फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना में परेशानी होगी।

इस्राइल ने यरूशलम के पास एक निर्माण प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह एक विवादित प्रोजेक्ट है, जिसके पूरे होने के बाद वेस्ट बैंक दो हिस्सों में बंट जाएगा। इस्राइल की इस योजना का विरोध हो रहा है। हालांकि सारे विरोध को दरकिनार कर इस्राइल की सरकार ने इसका टेंडर निकाल दिया है। इस्राइली बस्तियों के चलते वेस्ट बैंक में बढ़ा संघर्ष गाजा और वेस्ट बैंक में इस्राइल के सेट्लमेंट्स की निगरानी करने वाले संगठन पीस नाउ ने दावा किया है कि इस्राइल की सरकार ने टेंडर निकाल दिए हैं। नीलामी के बाद एक निर्माण कंपनी को इस प्रोजेक्ट को दे दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक महीने के भीतर इस विवादित बस्ती का निर्माण शुरू हो सकता है। इस्राइल के इस प्रोजेक्ट से वेस्ट बैंक दो हिस्सों में बंट जाएगा और इससे फलस्तीन के गठन में समस्या हो सकती है। इस्राइल हमास के युद्ध के बाद से वेस्ट बैंक में इस्राइली बस्तियों में रहने वाले लोगों और वेस्ट बैंक के लोगों के बीच पहले ही संघर्ष बढ़ चुका है। अब इस प्रोजेक्ट के निर्माण के बाद बवाल बढ़ सकता है।

यूक्रेन में शांति के लिए पेरिस में हुई बैठक, मैक्रों बोले- युद्धविराम की दिशा में बड़ा कदम

पेरिस (एजेंसी)। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को रोकने के लिए पेरिस में हुई सुरक्षा बैठक में 25 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया। मैक्रों ने इस बैठक को युद्धविराम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। बैठक में रूस का यूक्रेन पर आक्रमण रोकने और शांति स्थापित करने की दिशा में अहम चर्चा हुई। लगभग चार साल से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष दिन-प्रतिदिन और घातक होता जा रहा है। दूसरी ओर जारी इस संघर्ष में ताबड़तोड़ हमले ने दुनियाभर में चिंता का माहौल बना रखा है। इसी बीच इस संघर्ष को थामने की दिशा में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई बैठक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के सहयोगी देशों के साथ पेरिस में हुई सुरक्षा बैठक रूस का यूक्रेन पर आक्रमण रोकने और शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मैक्रों ने बताया कि पेरिस में हुई इस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम की निगरानी, यूक्रेनी सेना को हथियार और प्रशिक्षण, बहुराष्ट्रीय बल तैनाती और भविष्य में रूस की आक्रामकता रोकने के उपायों पर चर्चा हुई। इस बैठक में अमेरिका सहित 25 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया। युद्धविराम का निगरानी करेगा अमेरिका बता दें कि बैठक में यह तय किया गया कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम की निगरानी अमेरिकी नेतृत्व में की जाएगी। सहयोगी देशों ने यह भी कहा कि युद्धविराम के बाद भी यूक्रेन की सेना को हथियार, प्रशिक्षण और समर्थन जारी रहेगा, ताकि वह भविष्य में रूस की किसी भी आक्रमण को रोक सके। रिपब्लिकन से क्या कहा? बैठक में तय किया गया कि जमीन, समुद्र और हवा में सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे, जब युद्धविराम विश्वसनीय तरीके से लागू हो जाएगा।

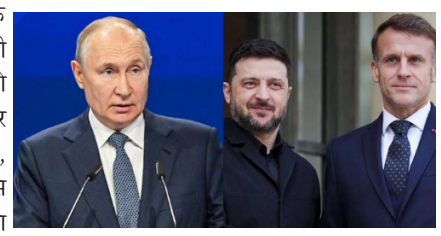

हालांकि, देशों को अभी बाध्यकारी वचन अंतिम रूप से तय करने हैं, ताकि भविष्य में रूस के हमले की स्थिति में यूक्रेन को सहायता दी जा सके। बैठक में बड़ी संख्या में शामिल हुए राष्ट्राध्यक्ष और सरकारी प्रतिनिधि मैक्रों ने आगे कहा किइस बैठक में अब तक की सबसे बड़ी संख्या में राष्ट्राध्यक्ष और सरकारी प्रतिनिधि शामिल हुए। अमेरिकी प्रतिनिधियों में स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुश्नर भी इस बैठक में शामिल हुए। इतना ही नहीं इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी मैक्रों के साथ बैठक की। जेलेंस्की ने यह बताया कि यूरोपीय देशों की सेना का सहयोग और प्रतिबद्धता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसी देशों की सैनिक तैनाती, हथियार और तकनीकी समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि कई देश अपने संसद से मंजूरी लेने के बाद ही सैनिक तैनात कर सकते हैं। इसलिए कुछ देशों की प्रतिबद्धता अभी स्पष्ट नहीं है। बैठक में पांच मुख्य मुद्दों पर दिया गया जोर, रूस का क्या है रुख गौरतलब है कि इस बैठक के दौरान पांच मुख्य मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें युद्धविराम की निगरानी सुनिश्चित करना, यूक्रेनी सेना को दीर्घकालिक समर्थन प्रदान करना और भूमि, समुद्र और हवा में बहुराष्ट्रीय बल की तैनाती शामिल थी। इसके अलावा, भविष्य में रूस की किसी भी आक्रामकता की स्थिति में सुरक्षा वचन सुनिश्चित करने और यूक्रेन के साथ लंबे समय तक रक्षा सहयोग बनाए रखने पर भी चर्चा हुई। हालांकि, कमहत्वपूर्ण विवरण अभी तय नहीं हुए हैं।

यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए ट्रंप के दूत विटकॉफ से मिले जेलेंस्की, समर्थन के लिए यूएस को कहा धन्यवाद

पेरिस (एजेंसी)। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पेरिस में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्ति, सुरक्षा गारंटी, युद्धविराम की निगरानी और देश के पुनर्निर्माण पर विचार किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने मंगलवार को पेरिस में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में दोनों पक्षों ने मुख्य रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की। साथ ही दोनों पक्षों ने सुरक्षा गारंटी, युद्धविराम की निगरानी और देश के पुनर्निर्माण जैसे अहम मुद्दों पर विचार किया। इस दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और इसे युद्ध समाप्ति की

दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका सुरक्षा गारंटी, युद्धविराम की निगरानी और देश के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए तैयार है। आगे जेलेंस्की ने इस बात पर भी जोर दिया कि सात जनवरी को पेरिस में दोनों देशों की टीमें फिर से सुरक्षा गारंटी और युद्ध समाप्ति के लिए बुनियादी ढांचे पर काम जारी रखेंगी। यूक्रेन की तरफ से कौन-कौन लोग थे शामिल बता दें कि इस बैठक में यूक्रेन की ओर से कार्यालय प्रमुख किरिलो बुडानोव, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तेम उमेरोव, जनरल आंद्रेई ह्नातोव, कार्यालय के पहले उप प्रमुख सर्गी किसलित्स्या और राष्ट्रपति कार्यालय के सलाहकार ओलेक्सांद्र बेव्ज शामिल थे। ट्रंप के दूत स्टीव विटकोफ ने क्या कहा? वहीं इस बैठक के बाद अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकोफ ने कहा कि उनकी टीम ने यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल और कोएलिशन ऑफ द विलिंग के साथ बैठक की, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना को आगे बढ़ाया जा सके।

हादी के दल ने पुलिस के आरोपों से इनकार किया

इंसाफ न मिलने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेशी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में उनकी पार्टी इंकलाब मंच ने पुलिस जांच को नकार दिया है। इंकलाब मंच ने आरोप लगाया है कि हत्या में सरकारी तंत्र की मिलीभगत है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। बांग्लादेश में मारे गए छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की पार्टी 'इंकलाब मंच' ने पुलिस के आरोप पत्र (चार्जशीट) को मानने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस हत्याकांड में केवल स्थानीय अपराधी ही नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र भी शामिल है। बंगाली समाचार पत्र 'प्रथम आलो' के अनुसार, इंकलाब मंच ने चेतावनी दी है कि अगर न्याय सुनिश्चित नहीं किया गया, तो उन्हें हिंसक आंदोलन करना पडेगा। क्या है पुलिस का कहना? ढाका महानगर पुलिस की अपराध शाखा ने मंगलवार को मुख्य संदिग्ध फैसल करीम मसूद सहित 17 लोगों के खिलाफ औपचारिक आरोप तय किए। पुलिस का कहना है

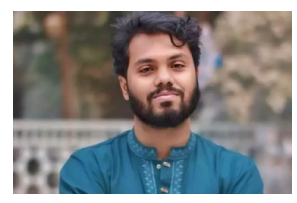

कि हादी की हत्या अवामी लीग के वार्ड पार्षद तैजुल इस्लाम चौधरी बप्पी के कहने पर 'राजनीतिक प्रतिशोध' के चलते की गई थी। पुलिस के अनुसार, कथित शूटर मसूद सीधे तौर पर अवामी लीग की छात्र इकाई से जुड़ा था। पार्टी के सचिव ने लगाया आरोप इंकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने पुलिस के दावे को हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि कोई विक्षिप्त व्यक्ति भी यह विश्वास नहीं करेगा कि हादी की हत्या केवल एक वार्ड पार्षद के निदेर्शों पर हुई। उन्होंने दावा किया कि इस हत्या में एक पूरा आपराधिक गिरोह और सरकारी तंत्र शामिल था। जाबेर ने कहा, ₹जब तक असली दोषियों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता तबतक हमारा संघर्ष नहीं रुकेगा।₹ कैसे शुरू हुआ मामला? बता दें कि जुलाई-अगस्त 2024 के विरोध प्रदर्शनों में प्रमुखता से उभरे 32 वर्षीय हादी को 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मारी गई थी। उपचार के दौरान 18 दिसंबर को सिंगापुर में उनका निधन हो गया।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharat?t=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. UPHIN/2016/67511 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा दीक्षित प्रिंटिंग प्रेस 120/51/1 मॉडल हाउस लखनऊ से मुद्रित एवं 233जी इंद्रलोक कॉलोनी कृष्ण नगर लखनऊ से प्रकाशित।
E-Mail : mantralko1008@gmail.com । सम्पादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे का क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।